● वर्ष-6

● अंक-85

रायपुर, बुधवार
04 नवंबर 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

|| संगछध्वम् संवदध्वम् ||

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-8›› विकसित भारत के निर्माण ..

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह में हुए शामिल

कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नक्सलवाद को मौन समर्थन दिया : अमित शाह

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में नक्सलवाद से मुक्त हुआ छत्तीसगढ़ अब विकास और सुशासन के स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है। शाह ने इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा असंवैधानिक सरकारों का समर्थन किया है। शाह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संवारने और विकसित करने का काम किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सभी लोगों, विशेषकर आदिवासी भाइयों और बहनों को बधाई दी। शाह ने कहा कि राज्य अब नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रयासों की सराहना की।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद के खतरे से मुक्त हो गया है। यह राज्य विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, और नरेंद्र मोदी ने इसे संवारने और विकसित करने का काम किया है। शाह ने छत्तीसगढ़ के लोगों, विशेषकर आदिवासी समुदाय को बधाई दी।



उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रयासों के लिए गहरी सराहना और आभार व्यक्त किया।

शाह ने कहा कि जिन क्षेत्रों में जनता की चुनी हुई सरकार नहीं थी, वहां नक्सलियों ने अपनी समानांतर सरकार चला रखी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नक्सलियों ने कई निर्दोष पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों को फांसी दी। शाह ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठाए।

गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नक्सलवाद को मौन समर्थन दिया है। उन्होंने 2010 में पी चिदंबरम के एक बयान का जिक्र किया। चिदंबरम ने कहा था कि नक्सलियों को हथियार डालने की जरूरत नहीं है, बस हिंसा न करें। शाह ने इस विचार को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह हिंसा नहीं रुकती। उन्होंने संसद में स्पष्ट कहा था कि जो भी आत्मसमर्पण करना चाहता है, वह हथियार डाल दे और मुख्यधारा में शामिल हो जाए। अन्यथा, हमारे जवान उनसे सख्ती से निपटेंगे।

अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और लोक परंपराओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास और गुरु नानक देव के संदेशों में समानता, सेवा और सत्य का भाव छत्तीसगढ़ की परंपरा का हिस्सा है।

विपक्ष को एसआईआर पर बहस की चुनौती

शाह ने कांग्रेस पार्टी पर संसद को लगातार बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संसद को बंधक बना रखा है। गृह मंत्री ने कहा, मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार हर एक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हम एसआईआर पर चर्चा के लिए एक विशेष सत्र बुलाने को भी तैयार हैं। शाह ने कांग्रेस से संसद को सुचारु रूप से चलने देने और उचित बहस में शामिल होने का आग्रह किया। शाह ने कांग्रेस से संसद को सुचारु रूप से चलने देने और उचित बहस में शामिल होने का आग्रह किया। गृह मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी ने हमेशा असंवैधानिक सरकारों का समर्थन किया है।

36 विभूतियां एवं संस्थाएं राज्य अलंकरण से किया सम्मानित

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के समापन समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों एवं संस्थाओं को प्रतिष्ठित राज्य अलंकरण पुरस्कारों से सम्मानित किया।

पंडित माधव राव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान रचनात्मक लेखन और हिन्दी भाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक श्री अनंत विजय को प्रदान किया गया। डॉ. तीज़न बाई सम्मान पंडवानी कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पाहंदा, दुर्ग जिले के श्री चेतन लाल देवांगन को प्रदान किया गया। चेंदरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कबीरधाम जिले के श्री सत्येन्द्र कुमार उपाध्याय सन्नी को प्रदान किया गया। संत रविदास सम्मान सामाजिक समरसता तथा साहित्य एवं काव्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बालोद जिले के श्री जगदीश प्रसाद देशमुख को प्रदान किया गया।



किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण - मोहन सुंदरानी। **बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान** - कौस्तुभ शुक्ला एवं हेमन्त कुमार मिश्र। **शहीद वीरनारायण सिंह स्मृति सम्मान**- डुमन लाल ध्रुव यति यतनलाल सम्मानविश्व गीता धेनू गोविन्द पक्षी सेवा धाम, कुम्हारी , गुण्डाधूर सम्मान संजू देवी । **मिनीमाता सम्मान**-लोक आस्था सेवा संस्थान, गरियाबंद (सुश्री लता नेताम)। **गुरु घासीदास सम्मान**-सुखचंद भास्कर। **ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार**-प्राथमिक कुडुक मछुवा सहकारी समिति मर्यादित, चित्रकोट। **हबीब तनवीर सम्मान** - डॉ. पुरुषोत्तम चन्द्राकर। महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान - टोमन कुमार । **पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान**- तेजस्विनी सेवा प्रतिष्ठान, नेहरू नगर । **पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान** -डॉ. बिहारीलाल साहू । **चक्रधर सम्मान** - डॉ. एम. श्रीराम मूर्ति। **दाऊ मंदराजी सम्मान** - श्रीमती रेखा जलक्षत्री। **डॉ. खूबचंद बघेल** -पुन्नीदास भट्ट। **महाराजा अग्रसेन सम्मान** - बाबूलाल अग्रवाल । **चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार**- प्रमोद कुमार साहू। **चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार हिन्दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया** - बरुण सखाजी एवं सुश्री रसिका पांडेय। **मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार अंग्रेजी प्रिंट मीडिया** -शिशिर रॉय चौधरी।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नई याचिका खारिज कर दी। इसमें उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में पाटन सीट से अपने निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान प्रारंभिक मुद्दा तय करने से इनकार करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने 28 सितंबर को भी पूर्व मुख्यमंत्री की उस याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने भाजपा नेता विजय बघेल की ओर से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को लेकर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती



दी थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मंगलवार को चुनाव याचिका की सुनवाई में देरी करने के प्रयासों पर नाराजगी जताई। पीठ ने कहा कि चुनाव याचिकाओं का निपटारा उचित समयसीमा के भीतर होना चाहिए। न्यायमूर्ति मोहना ने पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा से कहा कि मुकदमे को आगे बढ़ने दीजिए। आप जितना संभव हो सके, उतनी देरी कर रहे हैं। फैसला आएगा।

सिब्बल ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह मानकर गलती की कि प्रारंभिक मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत को या तो समयसीमा (लिमिटेशन) के सवाल को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय करना चाहिए या फिर यह नहीं कहना चाहिए कि ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। सिब्बल ने कहा, दो प्रार्थनाएं हैं। एक प्रारंभिक मुद्दे पर फैसला करने की है या फिर यह मत कहिए कि कोई मुद्दा नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई मुद्दा नहीं है।

पीठ ने उनकी दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति मोहना ने कहा कि समयसीमा का सवाल तथ्यों और कानून से जुड़ा मिला-जुला मुद्दा है। उन्होंने सवाल किया कि यह आपत्ति पहले क्यों नहीं उठाई गई। उन्होंने कहा, आप यह दलील पहले भी दे सकते थे। उन्होंने कहा कि उचित आधार के बिना कोई मुद्दा तय नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश ने भी सवाल किया कि बघेल ने संबंधित आपत्तियों को शामिल करने के लिए अपने लिखित बयान में संशोधन की मांग क्यों नहीं की।



रायपुर। तीन दिवसीय राज्योत्सव 2026 का शानदार आयोजन नवा रायपुर में हो रहा है। मुख्यमंच से हो रहे शानदार प्रस्तुतिकरण के तो क्या ही कहने। जनमानस इन बेहतरीन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिल्पग्राम, मीना बाजार और खाना खजाना में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। शिल्पग्राम की साज-सज्जा और उत्पाद लोगों को मुग्ध कर रहे हैं। मुख्य मंच के सामने ही बनाए गए मंच पर स्थानीय कलाकारों के संगीत की तान फिजा में माधुर्य घोल रही है। शिल्पग्राम में वैसे तो सेल्फी सेंटर बनाया गया है लेकिन पूरे शिल्पग्राम में ही लोग सेल्फी लेते हुए दिखाई देते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

56 चुनाव हारने के बाद भी नहीं स्वीकारी विफलता : स्मृति

कोलकाता। तीन नवंबर भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्हें 'निरंतर इंतजार में बैठे युवराज' करार दिया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर चुनावी हार को स्वीकार नहीं



करने का आरोप लगाया। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ प्रदर्शनों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि कांग्रेस ने मौजूदा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले 2014 से 2025 के बीच 56 चुनावों में हार का सामना किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने नेतृत्व की नाकामियों पर आत्ममंथन करने के बजाय अपनी चुनावी हार के लिए निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहरा रही है। भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, कांग्रेस 2014 से चुनाव हार रही है। उस समय ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी नहीं थे। मौजूदा एसआईआर से पहले 2014 से 2025 के बीच कांग्रेस 56 विधानसभा चुनाव हार चुकी है।

अखिलेश ने मतदान के दिन का मांगा सीसीटीवी लिंक

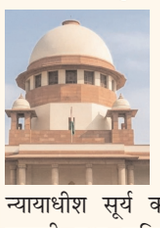
लखनऊ । सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदान के दिन पोलिंग बूथों की वेब कास्टिंग का लिंक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके लिए सपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने यूपी



के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मंगलवार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने 2027 के चुनाव में सभी 403 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के करीब 1 लाख 70 हजार पोलिंग बूथों पर वेब कास्टिंग और सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में वेब कास्टिंग का लिंक केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को मिलता है। इससे अधिकारी मतदान के दिन होने वाली घटनाओं और गड़बड़ियों को देख पाते हैं। हालांकि, राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को यह लिंक नहीं दिया जाता। इस कारण उन्हें बूथों पर होने वाली गड़बड़ियों की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। पार्टी ने इसे अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, अनैतिक और जनविरोधी बताया है। पार्टी ने पिछले उपचुनावों में हुई कथित गड़बड़ियों

अनिश्चितकाल तक धरना स्थल घेरना गलत : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए। यह कार्रवाई मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानश कुमार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर दिल्ली पुलिस की सख्ती को चुनौती देने वाली याचिकाओं की



सुनवाई के दौरान की गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी समूह विरोध प्रदर्शन के लिए किसी जगह पर अनिश्चित काल तक कब्जा करके नहीं बैठ सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, और जस्टिस जॉयमाल्य बागची तथा जस्टिस जेवी मोहना की पीठ ने किराना कमिटी दिल्लीकी एक याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें त्योहारों के मौसम के दौरान विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान विरोध करने के अधिकार, पुलिस की कथित ज्यादतियों, सार्वजनिक स्थानों पर पाबंदियों और प्रदर्शनों का व्यापार पर पड़ने वाले असर को लेकर तीखी बहस हुई। सुनवाई के दौरान, अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगहों के इस्तेमाल को लेकर अलग-अलग पक्षों के दावों पर विचार किया।

दो पर्चे रद्द, राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाएंगे हरदीप पुरी

मध्यप्रदेश। ज्यसभा उपचुनाव में दो निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन पत्र मंगलवार को जांच के दौरान खारिज कर दिए गए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का उच्च सदन के लिए निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी और एक अन्य निर्दलीय ने पुरी के हलफनामे पर आपत्ति जताई थी जिसे निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया। भोपाल, दो नवंबर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सहित दो निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन पत्र मंगलवार को खारिज होने के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का मध्यप्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। एक अधिकारी ने बताया कि नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख पांच नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच के अंतिम दिन निर्दलीय उम्मीदवार कांते सयन्ना और कांग्रेस समर्थित राजकुमार लोहानी के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। इस बीच, दोनों निर्दलीय उम्मीदवारों और कांग्रेस नेता हेमंत कटारे ने पुरी के नामांकन पत्रों पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि उनके द्वारा दाखिल किया गया।



बाबरी बनेगी, हिम्मत है तो रोक लो...हुमायूं की खुली धमकी

आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता और नौदा (पश्चिम बंगाल) से विधायक हुमायूं कबीर ने एक बार फिर 6 दिसंबर को प्रस्तावित मस्जिद निर्माण स्थल पर बड़ा जलसा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि



प्रशासनिक अड़चनों और राजनीतिक विरोध के बावजूद वह इस कार्यक्रम को हर हाल में आयोजित करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस प्रोजेक्ट को लेकर उन्हें न केवल भारत, बल्कि कई मुस्लिम देशों से भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। 3 नवंबर को दिए अपने बयान में हुमायूं कबीर ने कहा कि यह सिर्फ उनके क्षेत्र का मामला नहीं है, बल्कि यह देश और दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बेहद संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा है। उन्होंने कहा कि यह पूरे भारत के मुसलमानों के लिए और वैश्विक स्तर पर बांग्लादेश, ओमान, कतर, दुबई और सऊदी अरब जैसे देशों में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक जज्बाती मुद्दा है। इन तमाम मुल्कों से लोगों ने मुझे बार-बार फोन करके हौसला दिया है। वे कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इसे जारी रखिए, हम आपके साथ खड़े हैं।

महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू-कश्मीर... देश के कई राज्यों में सियासी भूचाल

नई दिल्ली। कई राज्यों में सियासी हलचल तेज हो गई है। कहीं सरकार गिरने की आशंका जताई जा रही है तो कहीं कहा जा रहा है कि बड़ी-बड़ी पार्टियां टूट सकती हैं। मतलब दिवाली के बाद कई राज्यों में बड़ा धमाका होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में शादी रचाई नई दुल्हन के पांव पड़े ही थे कि पार्टी के 21 विधायक बागी हो गए। उमर अब्दुल्ला बेचारे हनीमून पैकेज तलाश रहे थे कि उधर खबर आ गई कि पार्टी के बागी विधायकों ने दिल्ली से मिलने के लिए समय मांगा है। मतलब जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा बवाल देखने के लिए मिल सकता है। सरकार गिर सकती है। जिस तरह फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो तो पाकिस्तान है जिसने कश्मीरियों को बचाया। वहीं पर ये तय हो गया था कि चूक हो गई है। अब ऊपर से बयान आ रहा है कि 370 हटने से हालात खराब हुए। अब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में वही हालात पैदा करना चाहती है जो 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ। तो जरा सोचिए कि देश के लोग क्या सोचेंगे कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। त्यौहार मनाए जा रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी मनाए जा रहे हैं। टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है। इन्वेस्टमेंट बढ़ा है वो ज्यादा अच्छा सिचुएशन है या उससे पहले वाला सिचुएशन अच्छा था जब पुलिस वालों पर पत्थर मारे जाते थे। अभी हालात ज्यादा अच्छे हैं। लोग खुश नजर आ रहे हैं। उससे बेहतर क्या चाहिए?



महाराष्ट्र

उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे ने देवेंद्र फडनवीस से वन टू वन मुलाकात की वहां कमरे में मुलाकात हुई। उसके बाद एक मुलाकात और हुई एनसीपी अजीत पवार गुट के बड़े नेता जिसमें छगन भोजबल, प्रफुल पटेल और सबसे खास बात ये कि यह सब दिल्ली आए और दिल्ली में मुलाकात हुई है। मतलब अमित शाह से मुलाकात की है इन लोगों ने। अजीत दादा पवार की पत्नी सुनेत्रा की इच्छा है कि उनका बेटा एनसीपी में सब कुछ संभाले। जो पुराने नेता हैं जिन्होंने अजीत पवार के साथ मिलकर पार्टी तोड़ी और एनडीए के साथ आए उनका क्या? ऐसे में एक तरफ मां बेटे और एक तरफ बाकी नेता है। एक और टूट एनसीपी की तय है। बड़ा खेला मतलब महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल सकता है।

बिहार

बिहार में जेडीयू के दो गुट बनते दिख रहे हैं। अनंत सिंह को अभी निकाला गया। ललन सिंह और अनंत सिंह एक गुट के बताए जा रहे थेय् उन दोनों में अशोक चौधरी को किनारे कर दिया गया। संजय झा नीरज कुमार को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं जो कि अनंत सिंह समर्थित प्रत्याशी को रहा दिया है। तो तो साफ-साफ दिख रहा है दो गुट हैं। आपको पता है कि जेडीयू को हराने वाले कैंडिडेट बीजेपी में शामिल हो गए हैं। निर्दलीय से लड़े थे पर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। किसे पता कब क्या होगा? बिहार के भी जेडीयू का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आया है और वह भी मुलाकात करके जा चुका है। अब नीतीश कुमार एक तरफ हैं। नीतीश कुमार किसके ऊपर हाथ रखते हैं वो तो सबको पता है कि वो तो नीतीश कुमार सिर्फ जानेंगे।

पंजाब

पंजाब में कल देखा गया कि बीते दिन तीन विधायक आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हो गए। अकाली दल अप्रोच कर रही है कि किसी तरह बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन हो जाए। लेकिन बीजेपी ये कैलकुलेट कर रही है कि चुनाव के पहले अलायंस करने में फायदा है या चुनाव के बाद अलायंस करने में फायदा है। बीजेपी के कैलकुलेशन के अनुसार ही जो होना है वो होगा हम मतलब मतलब कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के कुछ लोग टूटने के लिए तैयार हैं और दूसरा बीजेपी ये कैलकुलेट कर रही है कि अकाली दल अलग लड़े तब फायदा है या साथ में मिलके प्री अलायंस हो या पोस्ट अलायंस हो अलायंस होगा।

कलेक्ट्रेट जनदर्शन में पहुंचे भुंजिया जनजाति

■ हर काम के लिए दूसरे जिले का चक्कर काटने से है परेशान, परियोजना कार्यालय शिफ्ट करने की मांग



धमतरी। जिले के वनांचल नगरी क्षेत्र में रहने वाले पीवीटीजी दर्जा प्राप्त भुंजिया समुदाय के करीब 450 परिवार आज अपनी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट जनदर्शन में पहुंचे।

इस दौरान उन्होंने प्रशासन को आवेदन सौंपकर परियोजना कार्यालय को गरियाबंद से धमतरी जिले में स्थानांतरित करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से ही उन्हें विभिन्न शासकीय कार्यों के लिए गरियाबंद जिले के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वनांचल नगरी क्षेत्र में भुंजिया जनजाति के लगभग 450 परिवार निवास करते हैं, जिन्हें अपने कार्यों के लिए दूर स्थित गरियाबंद जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष पिछड़ी जनजाति का परियोजना कार्यालय धमतरी जिले के नगरी में स्थापित किया जाए, ताकि उन्हें शासकीय योजनाओं और अन्य जरूरी कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।

वहीं पूरे मामले पर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा का कहना है कि छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या आधार पर परियोजना कार्यालय बनाए गए थे।

मूल रूप से गरियाबंद में भूंजीया जनजाति अधिक संख्या में निवास करती है इसलिए परियोजना कार्यालय को गरियाबंद में स्थापित किया गया है। आज कुछ ग्रामीण एक कार्यालय को नगरी में खोलने की मांग लेकर पहुंचे थे, चूंकि यह विशेष पिछड़ी जनजाति का मामला है इसलिए आवेदन की उच्चस्तर पर प्रेषित किया गया है।

नपं से अलग होकर ग्राम पंचायत बनाने की मांग

बालोद। जिले के डौंडी नगर पंचायत में पांच वार्डों के सैकड़ों लोगों ने नगर पंचायत से अलग होकर स्वतंत्र ग्राम पंचायत बनाने की मांग को लेकर मंगलवार को नगर पंचायत कार्यालय का घेराव किया। वार्ड क्रमांक 8, 9, 10, 11 और 15 के रहवासियों ने एकजुट होकर अपनी मांग रखी और नगर पंचायत से अलग होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे इस संबंध में तीन बार आवेदन लेकर नगर पंचायत कार्यालय पहुंच चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है। उनका कहना है कि नगर पंचायत में शामिल होने के बावजूद उनके वार्डों में विकास कार्य और रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, नगर पंचायत क्षेत्र में रहने के कारण उन्हें अधिक टैक्स देना पड़ता है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसके बावजूद उनके वार्डों में ऐसे काम नहीं हो रहे हैं, जिनसे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। ग्रामीणों का मानना है कि ग्राम पंचायत बनने से उन्हें स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों और रोजगार के अवसरों का लाभ मिल सकेगा।

नायब तहसीलदार पर गिरी निलंबन की गाज

सूरजपुर। सूरजपुर में सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद बवाल के मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासनिक लापरवाही के मामले में सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने नायब तहसीलदार करमचंद जाटवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। करमचंद जाटवर बिहारपुर में प्रभारी तहसीलदार के पद पर पदस्थ थे।



जानकारी के अनुसार, 17 अक्टूबर को ग्राम कुबेरपुर में ट्रैक्टर दुर्घटना के बाद उत्पन्न कानून-व्यवस्था की स्थिति को संभालने में देरी और लापरवाही बरतने का मामला सामने आया था। इस संबंध में मिली शिकायत और जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रशासनिक शिथिलता और कर्तव्य के प्रति उदासीनता पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है।संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नायब तहसीलदार करमचंद जाटवर को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पटवारी प्रशिक्षण शाला, अंबिकापुर निर्धारित किया गया है।

बता दें कि चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुबेरपुर में 17 अक्टूबर को स्कूटी सवार चंद्रावती जायसवाल को गिट्टी लोड ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसा इतना भीषण था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी और चालक मौके से वाहन समेत फरार हो गया था। कुछ देर बाद ग्रामीणों ग्रामीणों ने बस्ती से क्रशर को हटाने और मृतका के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया।

इतना ही नहीं ग्रामीणों ने बाद में ट्रैक्टर और पाठक क्रशर में आग लगा दी थी। जानकारी पर मौके में पहुंची पुलिस और प्रशासन टीम ने स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने बिहारपुर तहसीलदार करमचंद जाटवर, एसडीओपी और थाना प्रभारी लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता को बंधक बना लिया था। इधर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने घटना के बाद चक्काजाम और आगजनी मामले में ग्रामीणों पर हुई कार्रवाई को लेकर पुलिस-प्रशासन को जमकर फटकार लगाई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब घटना दोपहर 12 बजे हुई और आगजनी शाम 6 बजे हुई, तब तक पुलिस-प्रशासन क्या कर रहा था ? मंत्री ने यह भी कहा था कि तीन दिन में छह ग्रामीणों को जेल भेज दिया गया, लेकिन अब तक यह पता नहीं लगाया जा सका कि संबंधित क्रशर वैध है या नहीं।मंत्री राजवाड़े ने हादसे के जिम्मेदार ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई थी और पुलिस की कार्रवाई को एकतरफा बताते हुए उन्होंने ग्रामीणों पर जबरन फर्जी केस बनाकर फंसाने का आरोप लगाया था।

उन्होंने सवाल किया था कि भाजपा कार्यकर्ताओं को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है ? घटना के दौरान कांग्रेस के एक नेता के हाथ में लाठी लेकर दौड़ाने की बात सामने आई, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई ?

कवर्धा में धर्मांतरण के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रोटेस्ट



कवर्धा। अवैध तरीके से कराए जा रहे धर्मांतरण की कथित शिकायतों को लेकर एक बार कबीरधाम में विवाद गहरा गया है। नाराज ग्रामीणों ने आज कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर प्रदर्शन किया। गांव के प्रमुखों ने अपनी मांगों के समर्थन में कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा।

समाज प्रमुखों का आरोप था कि चोरी छिपे धर्म परिवर्तन की घटनाएं लगातार जारी हैं, जिसपर रोक लगाई जानी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कलेक्टर से मिलकर अपनी शिकायत करने वालों में 18 गांवों के समाज प्रमुख शामिल रहे। गांव के प्रमुखों ने जिला प्रशासन से कहा कि वो अवैध तरीके से होने वाले धर्मांतरण और उसको अंजाम देने वाले लोगों पर सख्ती बरतें। ग्रामीणों का आरोप था कि वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले भोले-भाले आदिवासियों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पैसों का लालच देकर तथा बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा। गांव के समाज प्रमुखों का कहना है कि कुछ स्थानों पर आर्थिक सहायता का प्रलोभन देकर लोगों की धार्मिक आस्था बदलने की कोशिश की जा रही है।

ग्रामीणों ने इस कथित गतिविधियों में लिप्त लोगों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि जो लोग सरकारी नौकरी में पदस्थ हैं और पैसे से मजबूत हैं, वो इस तरह की गतिविधियों में ज्यादा शामिल हैं। ग्रामीणों के इन आरोपों की पुष्टि हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से नहीं हुई है।

छग में पटवारियों की हड़ताल, निलंबन आदेश की कॉपी जलाकर विरोध



जांजगीर चांपा/धमतरी/बलरामपुर= छत्तीसगढ़ में 13 अक्टूबर से पटवारियों की हड़ताल जारी है। जांजगीर में 141 पटवारियों को जिला प्रशासन ने ब्रेक इन सर्विस, जिला अध्यक्ष और कार्यकारी प्रांताध्यक्ष के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला जांजगीर-चांपा ने पटवारियों के आंदोलन को समर्थन दिया है। फेडरेशन एवं राजस्व पटवारी संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने एकजुट होकर शासन के दंडात्मक कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया और निलंबन आदेश की प्रतियां जलाया। राजस्व पटवारी संघ पदोन्नति और वेतन विसंगति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार मांगों को ध्यान न देकर दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। भविष्य में यदि मांगों को नहीं माना जाता है तो कर्मचारी, अधिकारी बैनर तले आंदोलन और उग्र होगा -विश्व नाथ सिंह परिहार, जिला संयोजक अधिकारी फेडरेशन धमतरी में 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पटवारियों के खिलाफ अब शासन-प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। धमतरी जिले में दो पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं हड़ताल में शामिल धमतरी, नगरी, कुरूद सहित विभिन्न क्षेत्रों में पटवारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। धमतरी जिले में राजस्व पटवारी संघ के बैनर तले करीब 148 पटवारी हड़ताल पर हैं। नगरी और मगरलोड के दो पटवारियों पर निलंबन की गाज गिरी है। नगरी एसडीएम ने हल्का पांवद्वार में पदस्थ पटवारी चिम्मन लाल ध्रुव को निलंबित किया है। वहीं मगरलोड तहसीलदार ने मुख्यालय बेलोरा में पदस्थ पटवारी चैतन्य नेताम को निलंबित किया है। प्रशासन ने धमतरी, नगरी, मगरलोड, भखारा और कुकरेल क्षेत्र के पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पटवारियों को 48 घंटे के भीतर उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि कुछ दिनों पहले कार्य में लापरवाही के चलते कुछ पटवारियों को निलंबित किया गया है। बलरामपुर जिला मुख्यालय में पटवारियों ने निलंबन कार्यवाही के आदेश की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जताया। बलरामपुर जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन के दौरान पटवारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता विनय पांडेय ने कहा कि गिरदावरी में हो रही व्यवहारिक परेशानियों को लेकर प्रशासन को मांग बताने के लिए 13 अक्टूबर से आंदोलन शुरू किया है, लेकिन हमारे प्रांताध्यक्ष को निलंबित किया गया और दमनकारी नीति अपनाई गई है। जिलाध्यक्ष सहित चार अन्य पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कुसमी में भी तीन पटवारियों को निलंबित किया गया है। बलरामपुर राजस्व पटवारी संघ की तहसील अध्यक्ष सुरभि दास ने कहा कि हम अपनी दो जायज मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। पटवारी का पद ऐसा पद है जो जिस पद पर ज्वाइन होते हैं उसी पद पर रिटायर हो जाते हैं मतलब हमारी जिंदगी में कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। पटवारियों के हड़ताल की वजह से छत्तीसगढ़ में आगामी 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी की प्रक्रिया के साथ गिरदावरी और राजस्व विभाग से संबंधित तमाम जरूरी जांच प्रतिवेदन, आय, जाति, निवास सहित अन्य आवश्यक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

प्रत्रकार पर लाठी भांजने वाला सीएएफ जवान निलम्बित



खैरागढ़। राज्योत्सव समारोह कवर करने के लिए पत्रकार से मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार किशोर सोनी के साथ हुई मारपीट से नाराज जिले भर के पत्रकारों ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। फतेह सिंह मैदान के मुख्य गेट पर करीब दो घंटे तक धरना-प्रदर्शन कर पत्रकारों ने दोषी ड्यूटी जवान के तत्काल निलंबन की मांग उठाई। पत्रकारों के कड़े विरोध के बाद संबंधित ड्यूटी जवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल को स्वयं धरना स्थल पर पहुंचकर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने पत्रकारों की समस्याएं सुनीं और पूर्व में सौंपे गए ज्ञापनों सहित पुरानी मांगों पर भी कार्रवाई का आश्वासन दिया। पूरा मामला जिला प्रशासन के तीन दिवसीय जिला स्तरीय सरस मेले की कवरेज के दौरान का है। जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौर के अनुसार, वरिष्ठ पत्रकार किशोर सोनी कार्यक्रम की कवरेज के लिए फतेह सिंह मैदान पहुंचे थे। इसी दौरान बाइक को साइड करने की बात पर पुलिसकर्मियों ने उनके साथ कथित तौर पर गाली-गलौज और मारपीट की। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पत्रकारों में भारी आक्रोश फैल गया। इसके बाद सभी पत्रकार एकजुट होकर मैदान के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। उनकी स्पष्ट मांग थी कि मारपीट करने वाले ड्यूटी जवान को तत्काल निलंबित कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौर ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पत्रकार संघ पहले भी स्थानीय समस्याओं और दूसरी प्रशासनिक मामलों को लेकर कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उन पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

एसईसीएल में सफाई मित्र सम्मान समारोह आयोजित

बिलासपुर। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत एसईसीएल द्वारा संचालित स्पेशल कैंपेन 6 के अंतर्गत रविंद्र भवन, वसंत विहार, बिलासपुर में सफाई मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर श्री बिरंची दास ने सफाई मित्रों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छ एवं स्वस्थ कार्यस्थल के निर्माण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी से स्वच्छता को अपनी दैनिक कार्यशैली का हिस्सा बनाने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा लगभग 200 सफाई कर्मियों का सम्मान। मुख्य अतिथि एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन्हें सम्मानित कर उनके समर्पण, परिश्रम एवं योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि एसईसीएल में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान 6संचालित किया जा रहा है।

अनिश्चितकालिन हड़ताल की तैयारी में संयुक्त ड्राइवर संघ

जगदलपुर। बस्तर में संयुक्त ड्राइवर संघ ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है। संघ ने बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। हड़ताल से जरूरी सेवाओं पर असर हो सकता है। ड्राइवरों की हड़ताल से राशन वितरण, सब्जी मंडी, पेट्रोल-डीजल परिवहन, खनिज ढुलाई और यात्री बसों का संचालन प्रभावित होने की आशंका है। 33 जिलों के ड्राइवर संघ एकजुट होकर रायपुर में 33 जिलों के पदाधिकारियों की बैठक में हड़ताल का निर्णय लिया गया है। पहले भी मांगों को लेकर आंदोलन हुआ था, लेकिन आश्वासन के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। संघ का आरोप है कि चालकों को आए दिन मारपीट, झूठे आरोप और असुरक्षा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ड्राइवर आयोग, वेलफेयर और ड्राइवर दिवस की मांग भी प्रमुख है। अब देखना होगा कि 12 नवंबर से पहले शासन-प्रशासन ड्राइवरों की मांगों पर क्या निर्णय लेता है या नहीं।

दिवाली के लिए आपकी स्वादिष्ट मिठाईयां ऐसे हो रही तैयार

धमतरी। दिपावली त्यौहार से पहले खाद्य विभाग एक्शन मोड में आ गया है। धमतरी के दो दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों पर खाद्य विभाग की टीम औचक निरीक्षण किया। इस दौरान करीब 30 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, जिनकी जांच के लिए लैब भेजा गया है। जांच के दौरान कुछ जगहों पर गंदगी के बीच मिठाई और नमकीन तैयार होते मिले। दरअसल, त्यौहारी सीजन में बाजार में नकली पनीर, खोवा और अन्य खाद्य सामग्री में जमकर मिलावट की शिकायतें सामने आती हैं। ऐसे में खाद्य विभाग ने दो दर्जन से ज्यादा प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक कार्रवाई की है। स्थानों से संदिग्ध लगने पर सैंपल लिए गए, जिसकी जांच के लिए भेजा गया है। कुछ प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई के अभाव के बीच मिठाईयां और नमकीन तैयारी करते पाया गया। खाद्य विभाग की ओर से 4 संस्थानों को चेतावनी देते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। पिथौरा खाद्य अधिकारी फनेश्वर ने बताया कि लगभग 25 से 30 संस्थानों से खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा गया है।

शासन को लाखों के राजस्व नुकसान की आशंका

गरियाबंद। छुरा विख के ग्रापं पोंड़ में रेत के अवैध भंडारण और परिवहन का मामला सामने आया है। कुगदा बांध रोड स्थित एक निजी जमीन पर बड़ी मात्रा में रेत जमा होने और हाइवा वाहनों से परिवहन किए जाने का आरोप लगाया गया है। मामले में शासन को लाखों रुपये के खनिज राजस्व का नुकसान होने की आशंका जताई है। इस संबंध में भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रीतम सिन्हा ने सवाल उठाते हुए कहा कि ग्राम पोंड़ में बड़े पैमाने पर रेत का भंडारण किसकी अनुमति से किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित कारोबारियों के पास भंडारण अनुज्ञप्ति, रॉयल्टी और परिवहन के लिए ई-ट्रांजिट पास जैसे जरूरी दस्तावेज होने की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। सिन्हा ने कहा कि खनिज संपदा के अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन पर नियंत्रण की जिम्मेदारी खनिज, राजस्व, परिवहन और पुलिस विभाग की है। इसके बावजूद यदि क्षेत्र में लंबे समय से रेत का भंडारण और हाइवा से परिवहन हो रहा है तो संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था पर

20 नवंबर को तुलसी विवाह पर रहेगा स्थानीय अवकाश

जगदलपुर। बस्तर जिले में स्थानीय अवकाश को लेकर जिला प्रशासन ने एक संशोधित आदेश जारी किया है। कलेक्टर श्री आकाश छिकारा द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार जिले में पूर्व निर्धारित स्थानीय अवकाश की तारीख में बदलाव करते हुए अब 20 नवंबर को अवकाश घोषित किया गया है। पूर्व में जिला प्रशासन ने 11 फरवरी के एक आदेश के माध्यम से 9 नवंबर (सोमवार) को गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश देने का निर्णय लिया था। हालांकि राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत 9 नवंबर को पहले ही पूरे राज्य में गोवर्धन पूजा का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा चुका है। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर 9 नवंबर को दिए गए स्थानीय अवकाश को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है और अब निरस्त अवकाश के बदले 20 नवंबर शुक्रवार को तुलसी विवाह के पावन अवसर पर संपूर्ण बस्तर जिले के लिए स्थानीय अवकाश रहेगा।

गरियाबंद राज्योत्सव में नहीं दिखी उम्मीद के मुताबिक जनभागीदारी

■ मंच सजा, लेकिन खाली रह गईं कुर्सियां!



गरियाबंद। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ियों की पहचान, अस्मिता, संघर्ष और गौरव का उत्सव है। हर साल 1 नवंबर को पूरा प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। मध्यप्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ ने 26 वर्षों का सफर पूरा कर लिया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अलग राज्य गठन का सपना साकार हुआ और तभी से राज्योत्सव छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन गरियाबंद में इस बार राज्योत्सव के आयोजन स्थल को लेकर एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है, जिसकी चर्चा अब आम लोगों के बीच होने लगी है।

दरअसल, अब तक जिला मुख्यालय गरियाबंद में होने वाले राज्योत्सव का आयोजन इस बार शहर से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर पुलिस परेड ग्राउंड में किया गया। जगह बदली, मंच सजा, रोशनी हुई, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, विभागीय प्रदर्शनियां लगीं और अतिथियों की मौजूदगी में आयोजन भी संपन्न हुआ। लेकिन इस पूरे आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही रहा कि आखिर आम जनता कितनी संख्या में इस उत्सव का हिस्सा बन पाई? पहले जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाले राज्योत्सव की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि आम नागरिकों को इसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती थी। बाजार या किसी दूसरे काम से निकले लोग भी कुछ देर रुककर सांस्कृतिक कार्यक्रम देख लेते थे। शाम होते ही परिवार के साथ लोग पहुंच जाते थे। बुजुर्ग अपने छोटे बच्चों को लेकर आते थे। महिलाएं, युवा और आम नागरिक छत्तीसगढ़ी गीत-संगीत और लोक संस्कृति का आनंद लेते थे। लेकिन इस बार आयोजन स्थल शहर से दूर होने के कारण कई लोगों के सामने आने-जाने की असुविधा का सवाल खड़ा हुआ। कुछ लोग आपस में चर्चा करते नजर आए कि इतनी दूर कौन जाए, कैसे जाए और परिवार के साथ पहुंचना कितना सुविधाजनक होगा? हालांकि यह कहना भी उचित नहीं होगा कि दूरी ही कम उपस्थिति का एकमात्र कारण रही, लेकिन आयोजन स्थल की पहुंच पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। राज्योत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और कार्यक्रमों की तैयारी अपनी जगह थी, लेकिन दर्शक दीर्घा में नजर आने वाली खाली कुर्सियां आयोजन की जनभागीदारी को लेकर चर्चा का विषय बन गईं। मंच पर कार्यक्रम चलता रहा, प्रस्तुतियां होती रहीं, अतिथियों के संबोधन भी हुए, लेकिन दर्शकों की मौजूदगी को लेकर जो तस्वीर सामने आई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। सरकारी आयोजन की सफलता का आकलन केवल मंच की भव्यता, लाइटिंग, साउंड सिस्टम और अतिथियों की संख्या से नहीं होना चाहिए। असली सफलता तब है, जब आम नागरिक भी पूरे उत्साह के साथ उसमें शामिल हो।

पंडरिया के दामापुर में उप तहसील कार्यालय शुरू

कवर्धा। कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड अंतर्गत दामापुर में छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर ग्रामीणों को बड़ी सौगात मिली। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने उप तहसील कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। ग्रामीणों की इस बहुप्रतीक्षित मांग के पूरा होने पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि दामापुर में उप तहसील कार्यालय की शुरुआत क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी सौगात है। अब लोगों को जमीन और राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर ही शासकीय कामकाज की सुविधा मिलने से ग्रामीणों का समय और पैसा बचेगा तथा उनकी समस्याओं का निराकरण भी सुगम होगा।

उप तहसील कार्यालय के शुरू होने से दामापुर सहित आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें जमीन और राजस्व से जुड़े कार्यों के लिए पंडरिया तहसील कार्यालय तक लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। क्षेत्र के लोगों को स्थानीय



स्तर पर ही राजस्व संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। दामापुर क्षेत्र पंडरिया विकासखंड के बड़े ग्रामीण इलाकों में शामिल है। आसपास के कई गांवों के लोग विभिन्न शासकीय और राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दामापुर पर निर्भर रहते हैं। अब तक छोटे-बड़े राजस्व कार्यों के लिए ग्रामीणों को पंडरिया जाना पड़ता था। इससे उन्हें आने-जाने में समय और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। क्षेत्रवासी लंबे समय से दामापुर में उप तहसील कार्यालय शुरू करने की मांग कर रहे थे। विधायक ने इस सौगात के लिए क्षेत्रवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे।

राज्य निर्माण के प्रणेता अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान अविस्मरणीय : देव

सशक्त नारी, युवा उड़ान के संकल्प के साथ जगदलपुर में गूंजा विकास का शंखनाद

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 26 वें गौरवशाली वर्ष के अवसर पर बस्तर जिले के जिला मुख्यालय जगदलपुर में सशक्त नारी, युवा उड़ान की केंद्रीय थीम पर जिला स्तरीय राज्योत्सव 2026 का आयोजन हुआ। इस आयोजन में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आम नागरिकों ने मिलकर बस्तर को संघर्ष के दौर से बाहर निकालकर स्थायी समृद्धि की ओर ले जाने का दृढ़ संकल्प दोहराया। समारोह के शुभारंभ में जगदलपुर विधायक श्री किरण सिंह देव ने राज्य निर्माण के प्रणेता भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करते हुए कहा कि श्री बाजपेयी ने छत्तीसगढ़ वासियों के सरल स्वभाव और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए बिना किसी बड़े संघर्ष के इस राज्य की सौगात दी थी।

विधायक श्री देव ने प्रदेश के विकास को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का सीधा लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने अपने वादे के अनुरूप 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की व्यवस्था की है, वहीं महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख से अधिक माताओं-बहनों के बैंक खातों में हर माह 1000 रुपए भेजकर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए जगदलपुर में 24 घंटे संचालित होने वाली नालंदा परिसर जैसी आधुनिक अध्ययन सुविधाएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में युवाओं के लिए सहायक साबित होगी। इसके साथ ही धुरवा जनजाति बहुल क्षेत्र धुड़मारास के हेरिटेज विलेज चयन, होम-स्टे और पर्यटन कॉरिडोर के विकास से स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं।

राज्योत्सव समारोह को संबोधित करते हुए नगर पालिक निगम जगदलपुर के महापौर श्री संजय पाण्डे ने नारी शक्ति और युवा ऊर्जा को नए बस्तर के निर्माण का सबसे सशक्त आधार बताया। उन्होंने कहा कि दशकों तक माओवाद हिंसा का दंश झेलने वाला यह अंचल अब पूरी तरह भयमुक्त होकर शांति और विकास के नए आयाम की ओर अग्रसर है। आज बस्तर की बेटियां देश की सीमाओं की रक्षा से लेकर खेल के



मैदानों, नवाचार, स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया के मंचों पर तिरंगे का मान बढ़ा रही हैं। महापौर ने रेखांकित किया कि बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसी पहलों ने स्थानीय प्रतिभाओं को नई पहचान दी है, जिससे आज का युवा नौकरी तलाशने वाले के स्थान पर अपने कौशल और तकनीक के बल पर रोजगार प्रदाता बनकर उभर रहा है।

बस्तर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने जिले की विकास यात्रा को रेखांकित करते बताया कि सुरक्षा बलों के सर्वोच्च बलिदान और जनसहयोग के फलस्वरूप 31 मार्च 2026 को बस्तर क्षेत्र का माओवाद मुक्त होना एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ है, जिसके बाद प्रशासन का पूरा ध्यान शांति और त्वरित विकास में बदलने पर केंद्रित है। उन्होंने जिले की प्रगति की जानकारी प्रदान की।उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 8,700 करोड़ रुपए की लागत से अंदरूनी क्षेत्रों तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। गीदम-भोपालपटनम फोरलेन कॉरिडोर और अंतागढ़-जगदलपुर रेल परियोजना पर कार्य तेज गति से जारी है, जबकि राजधानी रायपुर और हैदराबाद के लिए नियमित हवाई सेवाएं क्षेत्र को नई गति दे रही हैं। इसके अलावा बस्तर मावा अभियान, पूना नर्कोम, 10,000 से अधिक देवगुड़ी व मातागुड़ी स्थलों का संरक्षण और मेडिकल कॉलेज व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जैसी अधोसंरचनाएं बस्तर में जनमानस के जीवन स्तर को लगातार उन्नत कर रही हैं। साथ ही देऊरगांव एवं मटनार सिचांई परियोजना से बस्तर में कृषि को एक नई दिशा मिलेगी। वर्ष 2031 तक बस्तर के प्रत्येक गांव को सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं से परिपूर्ण कर इसे पूर्णतः विकसित अंचल बनाने का संकल्प दोहराया।

इस दौरान समारोह में अतिथियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन कर आम जनता से जनहितकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। इस मौके पर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, भूमि स्वामित्व दस्तावेज सहित अन्य सहायता प्रदान की गई। वहीं बस्तर की आराध्य देवी मां दन्तेश्वरी के दर्शन हेतु जाने वाले श्रद्धालुओं हेतु संचालित पदयात्री सेवा केन्द्र में विभिन्न व्यवस्था सुनिश्चित करने वाले समाजसेवी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा गणमान्य नागरिकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूली बच्चों तथा पारम्परिक लोक कलाकरों को पुरस्कृत कर उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर नगर निगम सभापति श्री खेमसिंह देवांगन सहित क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि और कमिश्नर बस्तर श्री डोमन सिंह, आईजी श्री बद्रीनारायण मीणा, जिला पंचायत सीईओ श्री तन्मय खन्ना समेत जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

संक्षिप्त समाचार

केंद्रीय गृहमंत्री शाह पहुंचे रायपुर मुख्यमंत्री साय ने किया स्वागत



रायपुर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह मंगलवार की दोपहर को माता कौशल्या की पावन भूमि एवं प्रभु श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री साय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि छत्तीसगढ़ के प्रति आपका आत्मीय स्नेह हम सभी के लिए शक्ति और विश्वास का संबल है। प्रदेश की शांति, सुरक्षा और विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता एवं सतत सहयोग विकसित छत्तीसगढ़ के हमारे संकल्प को नई शक्ति और प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं को नया विश्वास प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ महतारी की इस पुण्य धरा पर आपका समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत है।

देवउठनी एकादशी पर स्थानीय अवकाश घोषित, सरकारी कार्यालयों में रहेगी छुट्टी

रायपुर। राज्य सरकार ने रायपुर और नवा रायपुर अटल नगर के शासकीय कार्यालयों के लिए स्थानीय अवकाश की तारीख बदल दी है। अब देवउठनी एकादशी के अवसर पर 20 नवंबर शुक्रवार को स्थानीय छुट्टी रहेगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। इससे पहले सरकार ने 9 नवंबर सोमवार को गोवर्धन पूजा के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया था। बाद में गोवर्धन पूजा पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने 9 नवंबर की स्थानीय छुट्टी को बदलकर 20 नवंबर को किया है।

पीएम केयर्स योजना से मोनिका बघेल के खाते में पहुंचे 10 लाख रुपये

रायपुर। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत बालोद जिले की बालिका सुश्री मोनिका बघेल को 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की गई है। भारत सरकार की ओर से यह राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने मोनिका को डेमो चेक प्रदान किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपर कलेक्टर, जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला बाल संरक्षण अधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही गैर-संस्थागत देखरेख एवं संस्थागत देखरेख के संरक्षण अधिकारी, मिशन शक्ति के परियोजना समन्वयक, मिशन वात्सल्य के अधिकारी-कर्मचारी तथा मोनिका के संरक्षक भी मौजूद रहे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत 29 मई 2021 को कोविड-19 महामारी से प्रभावित उन बच्चों को सहायता देने के उद्देश्य से की गई थी, जिन्होंने महामारी के दौरान अपने माता-पिता, कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता को खो दिया था। योजना के तहत प्रत्येक पात्र बच्चे के नाम पर 10 लाख रुपये का कॉर्पस फंड तैयार किया जाता है। 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बच्चे को 23 वर्ष की आयु तक मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है। 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कॉर्पस फंड की 10 लाख रुपये की राशि एकमुश्त प्रदान की जाती है।

रायपुर जिले में उचित मूल्य दुकानों से शक्कर की आपूर्ति एवं वितरण जारी

रायपुर। रायपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में शक्कर की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रूप से संचालित हो रही है। जिला प्रशासन और खाद्य विभाग द्वारा जिले में शक्कर की आपूर्ति व वितरण प्रक्रिया पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है, ताकि पात्र हितग्राहियों को तय व्यवस्था के अनुरूप समय पर राशन सामग्री प्राप्त हो सके और किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। खाद्य विभाग के जिला कार्यालय स्थित खाद्य शाखा द्वारा जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों में शक्कर के स्टॉक, उपलब्धता और वितरण की स्थिति की सतत समीक्षा की जा रही है। इस बीच, कुछ माध्यमों में जिले में शक्कर की आपूर्ति पूरी तरह बंद होने संबंधी भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही हैं, जो कि तथ्यहीन हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में शक्कर की उपलब्धता और वितरण का कार्य पूरी तरह सामान्य रूप से जारी है।

नक्सलवाद पर कांग्रेस को बोलने का हक नहीं प्रदेश के विकास का प्रमाण है खैरागांवः सीएम

रायपुर। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद सीएम साय ने मीडिया से बातचीत की। सीएम ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, जिन लोगों ने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया, जिन लोगों ने नक्सलवाद से लड़ने की कोई सार्थक नीति नहीं बनाई, उन लोगों को माओवाद पर बोलना नहीं चाहिए। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों को माओवाद पर बोलने से बचना चाहिए। सीएम ने कहा कि हमने माओवाद को खत्म करने में सफलता हासिल की।

विष्णु देव साय ने कहा कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए अब कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। देश को सिर्फ झूठ दिखाकर और बोलकर कांग्रेस ठगना चाहती है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की मंशा को जनता जान चुकी है और उनके झांसे में अब नहीं आने वाली। सीएम ने कहा कि जिन्होने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी वहीं लोग अब हमसे सवाल पूछ रहे हैं, बड़ी विडंबना है।

सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि हम लगातार विकास के कामों को बढ़ा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि



विकास के कामों में तेजी लाए जाए। सीएम ने कहा कि मैं दिल्ली दौरे से आज लौटा हूं।

मुख्यमंत्री ने कहा मैं दिल्ली गया था जहां पर ग्रीन एनर्जी को लेकर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी बात है कि राजनांदगांव जिले के खैरागांव को देश का पहला 100% ग्रीन ऊर्जा से आच्छादित गांव की सूची में शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के भारत मंडपम में भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट और एक्सपो 2026 का आयोजन था। इस आयोजन में हमें भी आमंत्रित किया गया था। समिट और एक्सपो में रिन्यूएबल एनर्जी को आगे ले जाने में जिस तरीके से काम हो रहा है, जिस तरह की तैयारी और तकनीक को विकसित किया जा रहा है, उस तरह की चीजों को देखने का मौका मिला। सीएम ने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी में छत्तीसगढ़ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी सरकार बिजली की जो खपत है उसमें 15त्न रिन्यूएबल एनर्जी से हो इसका प्रयास किया जा रहा है।

सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त घर बिजली योजना जो चलाई जा रही है, इस क्षेत्र में एक अच्छा प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी बात है कि जब से यह योजना लागू हुई है राजनांदगांव का खैरागांव प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना से लाभ ले रहा है। वहां के सारे घरों में सोलर प्लेट लगे हुए हैं और पूरा गांव ही सौर ऊर्जा से अपना काम करता है। सीएम ने कहा कि और आने वाले 5 वर्षों में 13 हजार 300 करोड़ के निवेश का लक्ष्य इस क्षेत्र में है। ऊर्जा के क्षेत्र में 5 लाख 60 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर काम छत्तीसगढ़ में चल रहा है।

राज्योत्सव में अमित शाह के लिए भीड़ जुटाने की हो रही कोशिशः कांग्रेस



रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का मंगलवार को तीसरा और अंतिम दिन था। समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को दिल्ली से रायपुर पहुंचे। केंद्रीय गृहमंत्री के राज्योत्सव के समापन समारोह में आने वाली भीड़ को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि अमित साह के कार्यक्रम को लेकर भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसा आरोप वो इसलिए लगा रही है कि समापन समारोह से पहले खाद्य विभाग का एक आदेश सामने आया है।

कांग्रेस के मुताबिक आदेश में खाद्य विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ राशन दुकान संचालकों को भी राज्योत्सव में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश मिले हैं। हालांकि इस आदेश के संबंध में कोई भी आधिकारिक बयान या दस्तावेज सामने नहीं आया है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से ठीक पहले जारी इस आदेश का सीधा मकसद सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। कांग्रेस का दावा है कि राज्योत्सव में लोगों की कम उपस्थिति की आशंका के चलते कर्मचारियों और राशन दुकान संचालकों को बुलाया जा रहा है। कांग्रेस के इन आरोपों पर फिलहाल बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

कांग्रेस का कहना है, रायपुर कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा से 2 नवंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि 3 नवंबर को राज्योत्सव के शासकीय कार्यक्रम में खाद्य विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी शाम 4 बजे से 7 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। आदेश में सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करने और कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी हैं। आदेश में कड़ाई से पालन करने की बात कही गई है।

कांग्रेस का आरोप है कि केवल खाद्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पीडीएस यानी राशन दुकानों के संचालकों को भी राज्योत्सव में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी का दावा है कि पंचायत और शिक्षा विभाग में भी इसी तरह के निर्देश जारी किए गए हैं।

कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ की जनता की कम भागीदारी को लेकर सरकार चिंतित है।

पीएम बनने का सपना देखकर सोते हैं राहुल गांधीः सतीश चंद्र दुबे



रायपुर। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्तमान समय में जो कांग्रेस को हेड कर रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रमुख हैं वह अर्ध पागल की स्थिति में है। उनको यह समझ ही नहीं आ रहा है कि वह कब और क्या बयान दे रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी किसी प्रदेश में 64 साल से किसी प्रदेश में 18 साल से लगातार चुनाव हार रहे हैं तब ये कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी का काम किया है। 2014 के बाद से लगातार चुनाव हार रहे हैं। यह पूरी कांग्रेस को पता है।

सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि ज्ञानेश कुमार ने हमें चुनाव हरवा दिया। वोट चोरी हो रहा है। ज्ञानेश कुमार जब कुर्सी पर आए हैं उसकी समय अवधि को देख लीजिए। कांग्रेस 2014 से लगातार चुनाव हार रही है। उसके पहले से कई राज्यों में उसकी हार हो रही है। उसके बाद यह बात कह रहे हैं कि उनके चुनाव के हारने का कराण ज्ञानेश कुमार है।जो 2014 और उससे पहले इस पद पर था वो इनके 40 साल से हार रहे चुनाव का कारण कैसे हो सकता है।

केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि कांग्रेस के लोग जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां सब कुछ अच्छा है। और जहां चुनाव हार जाते हैं वहां पर कहते रहते हैं की वोट चोरी हो गई। वहां पर आप कहते हैं कि लोकतंत्र खराब है। वोट चोरी हो रहा है। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि अगर वोट चोरी हो रहा है तो उसका प्रमाण दीजिए। जिसका कोई साक्ष्य इसके पास उपलब्ध नहीं है। प्रमाण नहीं देना है। सिर्फ बोलते रहना है तो इसका कोई मतलब नहीं है। केंद्रीय कोयला मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि जिस तरीके का बयान कांग्रेस के नेता दे रहे हैं और जब उसके लिए सबूत देने की बात आती है तो उनके हाथ कुछ नहीं होता। देश की जनता उनकी बात पर भरोसा नहीं करते हैं।

दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन ट्रेन के द्वितीय फेरे के परिचालन तिथि एवं गाड़ी संख्या में बदलाव

रायपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं बेहतर रेल परिचालन के मद्देनजर दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग पूजा स्पेशल ट्रेन के दूसरे फेरे के परिचालन की तिथि एवं गाड़ी संख्या में बदलाव किया गया है। गाड़ी संख्या 08751 दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन पूजा स्पेशल का परिचालन अब पूर्व निर्धारित तिथि 08 नवंबर 2026 (रविवार) के स्थान पर 05 नवंबर 2026 (गुरुवार) को 08753 नंबर के साथ किया जाएगा। इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 08752 हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग पूजा स्पेशल का परिचालन अब पूर्व निर्धारित तिथि 09 नवंबर 2026 (सोमवार) के स्थान पर 06 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को 08754 नंबर के साथ किया जाएगा।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर मण्डल क्रमांक 2 (छत्तीसगढ़)

ई-प्रोक्युरमेंट निविदा सूचना (प्रथम आमंत्रण)

दिनांक 31.10.2026

निम्न कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा "सी" एवं अधिक श्रेणी के ठेकेदारों के लिये आमंत्रित की जाती है। निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक 20.11.2026 तक है

एन.आई.टी. क्र./ निविदा क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत रू. (लाख में)
1	2	3
NIT NO. 246 Tender No. 203267	CONSTRUCTION OF JUDICIAL STAFF F-TYPE (01) , G- TYPE (02), H-TYPE (06), I-TYPE (04) Nos GOVT QTR'S INCLUDING ELECTRIFICATION WORK IN BASNA BLOCK AT DIST.-MAHASAMUND (C.G.)	रू. 162.48 लाख

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in अथवा विभागीय वेबसाइट https://eproc.cgstate.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। (राशि रू. 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र एवं न्यूनतम राशि रू. 10.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एनेक्जर-3 का शपथ पत्र, बिड केपेसीटी उपलब्धता बाबत् जानकारी एवं अन्य जानकारी एनआईटी के 2.10 में संलग्न संशोधित प्रपत्रानुसार प्रस्तुत करें।)

निविदों में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेग, एवं निविदाकारो द्वारा प्रेषित मूल अभिलेख का लिफाफा में निविवेकारों का मोबाईल नं. एवं इमेल आई.डी. का उल्लेख अनिवार्य रुप से करें।

Credible Chhattisgarh विश्वसनीय छत्तीसगढ़

जी-262704351/6

आपकी थी चाह, हमने बनाई राह

अधीक्षण अभियंता
लो.नि.वि. रायपुर मंडल क्र. 2 (छ.ग.)

मुरासु तूफान का असरः छत्तीसगढ़ में छाए रहेंगे बादल



रायपुर। छत्तीसगढ़ में फिर एक बार मुरासु तूफान की वजह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी के साथ ही बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण उमस और गर्मी बनी हुई है। इसके पहले चक्रवात अर्नब की वजह से 28 और 29 अक्टूबर को भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ था।

मौसम विभाग के मुताबिक मुरासु चक्रवात का असर छत्तीसगढ़ में ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। मुरासु चक्रवात बुधवार की सुबह लो प्रेशर में बदल जाएगा। मुरासु चक्रवात का सबसे ज्यादा असर आंध्र और तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। मुरासु चक्रवात का असर मंगलवार और बुधवार को दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में देखने को मिल सकता है। इस दौरान एक दो स्थानों पर हेवी रेन होने की संभावना है। 7 नवंबर के बाद मौसम ड्राई होने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आने के बाद छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ेगी।

मौसम वैज्ञानिक संजय बैरागी ने कहा चक्रवात मुरासु का ज्यादा असर आंध्र और तमिलनाडु में पड़ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका असर उतना ज्यादा नहीं होगा। दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में इसका असर देखने को मिल सकता है।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.- 5)
ईदगाहभाठा, नवीन पानी टंकी परिसर, रायपुर
Email ID - rmczonez@gmail.com
पत्र क्रं /....36617..../ न. पा. नि. जोन क्रं - 5/2026
रायपुर, दिनांक 03-11-2026
ईश्तहार
नामंतरण प्र.क्र. 36617
वार्ड का नाम 40 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 40 स्थित भवन / भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई. डी. RPR569B00581 जो की निगम अभिलेख श्री / श्रीमती KU. SAROJANI GAJBHIYE पिता / पति श्री श्रीमती YOURAJ GAJBHIYE के नाम से दर्ज है जिसको श्री / श्रीमती MANISH KUMAR BANSOD पिता / पति श्री/श्रीमती GOKUL DAS BANSOD ने मृत्यु प्रमाण पत्र सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार । पंजीकृत विक्रय विलेख / वंशानुक्रम / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते है, प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा / प्रस्तुत करे। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा / आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करे।
(जोन कमिश्नर) जोन (5)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.- 5)
ईदगाहभाठा, नवीन पानी टंकी परिसर, रायपुर
Email ID - rmczonez@gmail.com
पत्र क्रं /....36618..../ न. पा. नि. जोन क्रं - 5/2026
रायपुर, दिनांक 03-11-2026
ईश्तहार
नामंतरण प्र.क्र. 36618
वार्ड का नाम 41 - पं. सुंदर लाल शर्मा वार्ड

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 41 स्थित भवन / भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई. डी. RPR566D00217 जो की निगम अभिलेख श्री / श्रीमती RANJAN KUMAR PARADKAR पिता/पति श्री/श्रीमती LAXMAN PARADKAR के नाम से दर्ज है जिसको श्री / श्रीमती MEENAL MODI पिता / पति श्री श्रीमती LATE RANJAN KUMAR PARADKAR ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार । पंजीकृत विक्रय विलेख / वंशानुक्रम / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते है, प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा /प्रस्तुत करे । निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा / आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करे।
(जोन कमिश्नर) जोन (5) नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.- 5)
ईदगाहभाठा, नवीन पानी टंकी परिसर, रायपुर
Email ID - rmczonez@gmail.com
पत्र क्रं /....36056..../ न. पा. नि. जोन क्रं - 5/2026
रायपुर, दिनांक 03-11-2026
ईश्तहार
नामंतरण प्र.क्र. 36056
वार्ड का नाम 41 - पं. सुंदर लाल शर्मा वार्ड

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 41 स्थित भवन / भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई. डी. RPR566D00197 जो की निगम अभिलेख श्री / श्रीमती RAJ KUMAR DHURNDHAR पिता/पति श्री श्रीमती LATE. UMRAO SINGH DHURANDHAR के नाम से दर्ज है जिसको श्री / श्रीमती 1. ROHINI THAKUR W/O VEER SINGH THAKUR 2. MANOJ KUMAR THAKUR S/O VEER SINGH THAKUR 3. DEEPTI THAKUR D/O VEER SINGH THAKUR 4. BHUPENDRA SINGH THAKUR S/O VEER VEER SINGH THAKUR पिता / पति श्री/श्रीमती ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार / पंजीकृत विक्रय विलेख / वंशानुक्रम / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते है, प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा / प्रस्तुत करे । निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा / आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करे
(जोन कमिश्नर) जोन (5) नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.- 5)
ईदगाहभाठा, नवीन पानी टंकी परिसर, रायपुर
Email ID - rmczonez@gmail.com
पत्र क्रं /....36762..../ न. पा. नि. जोन क्रं - 5/2026
रायपुर, दिनांक 03-11-2026
ईश्तहार
नामंतरण प्र.क्र. 36762
वार्ड का नाम 68 - डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 68 स्थित भवन / भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई. डी. RPR567C00296 जो की निगम अभिलेख श्री / श्रीमती Meera bai thakre पिता/पति श्री श्रीमती Budhram thakre के नाम से दर्ज है जिसको श्री / श्रीमती AMIT KUMAR KHARE पिता /पति श्री श्रीमती ASHOK KUMAR KHARE ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार / पंजीकृत विक्रय विलेख / वंशानुक्रम / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते है, प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा /प्रस्तुत करे । निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा / आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जारी करे।
(जोन कमिश्नर) जोन (5)
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.- 5)
ईदगाहभाठा, नवीन पानी टंकी परिसर, रायपुर
Email ID - rmczonez@gmail.com
पत्र क्रं /....36701..../ न. पा. नि. जोन क्रं - 5/2026
रायपुर, दिनांक 03-11-2026
ईश्तहार
नामंतरण प्र.क्र. 36701
वार्ड का नाम 39 - ठाकुर प्यारे लाल वार्ड

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 39 स्थित भवन / भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई. डी. RPR569L00081 जो की निगम अभिलेख श्री / श्रीमती Kewal Ram Sahu पिता / पति श्री श्रीमती Jagannath Sahu के नाम से दर्ज है जिसको श्री / श्रीमती CHANCHALA VERMA पिता /पति श्री श्रीमती BHOLESHANKAR PRASAD VERMA ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बानामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार / पंजीकृत विक्रय विलेख / वंशानुक्रम / अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति / संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर

आरोपों के भंवर में उलझी सियासत और देश का भविष्य

राजकुमार सिंह

देश में राजनीतिक लड़ाई 'वोट चोरी बनाम अराजकता' के नैरेटिव तक सिमटती दिख रही है। सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों ही रविवार को सड़कों पर नजर आए। वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने मार्च निकालते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की तो भाजपा ने उसे 1984 के सिख दंगों से जोड़ते हुए देश भर में कांग्रेस के विरुद्ध मार्च निकाला। सड़क से गरमाती इस राजनीति की तपिश इसी माह शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में भी महसूस की जाएगी। वोट चोरी बनाम अराजकता के नैरेटिव की राजनीति कम-से-कम अगले साल होनेवाले विधानसभा चुनावों तक तो चलेगी। अगर विधानसभा चुनावों में इसका असर दिखा तो 2029 के लोकसभा चुनावों तक भी यह राजनीति खिंच सकती है। हालांकि दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली समेत आयोग की कार्यप्रणाली पर 10 महीनों में 14 बार आपत्ति के मीडिया में खुलासे के बाद यह विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। जाहिर है अदालती लड़ाई लंबी चलती हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' द्वारा 31 अक्तूबर को मॉक पार्लियामेंट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध महाभियोग पारित करने के अगले ही दिन रामलीला मैदान में रैली में तेवरों से साफ है कि विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देगा और सड़क पर भी लड़ाई जारी रखेगा। जवाब में भाजपा बेहद आक्रामक नजर आ रही है, लेकिन उसकी प्रतिक्रियाओं को इस मुद्दे पर उसके दबाव में होने के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। इसमें दो राय नहीं कि सिख दंगे एक दुखद और शर्मनाक घटनाक्रम रहा, पर क्या 1984 के बाद पंजाब में कई बार कांग्रेस सरकार बनना नहीं बताता कि सिख समुदाय कांग्रेस को अपने दुश्मन के रूप में नहीं देखता! दिल्ली में भी लगातार तीन बार कांग्रेस सरकार बिना सिख समुदाय के समर्थन के नहीं बन सकती थी। सिख दंगों के लिए मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए माफी मांगी थी तो खुद राहुल गांधी भी माफी मांग चुके हैं। बेशक सिख दंगों के आरोपियों को सजा दिलवाने में भाजपा और उसकी सरकार प्रयासरत दिखीं, लेकिन भाजपा ने एक नवंबर की रैली को सिख दंगों के मुद्दे पर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा का मौका शायद इसलिए भी बनाया क्योंकि पंजाब में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव हैं। भाजपा ने कांग्रेस को धनतेरस और दीपावली जैसे त्यौहारों के मद्देनजर भी कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की कि इससे खासकर रामलीला मैदान के नजदीकी चांदनी चौक और सदर बाजार जैसे बड़े बाजारों के दुकानदारों को हजारों करोड़ का नुकसान होगा। बेशक व्यापारियों के संगठन सीआईटी ने भी कांग्रेस को चार-चार पत्र लिखे कि रैली स्थगित कर दी जाए। कांग्रेस से हर्जाना मांगने की धमकी भी दी गई, लेकिन राहुल गांधी ने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा दिलवा दें, 30 सेकंड में रैली रद्द कर दी जाएगी। रैलीवाले दिन राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर रैली में भाग लेने आए लोगों से अपील की कि वे वापसी में दिल्ली के व्यापारियों से खरीददारी करें, लेकिन बाद में दूसरा वीडियो जारी कर दिल्ली पुलिस पर जबर्दस्ती दुकानें बंद करवाने का आरोप भी लगाया यानी नैरेटिव बनाने की कवायद में कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाह रहा। वोट चोरी के मुद्दे पर पूरा विपक्षी गठबंधन बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। रामलीला मैदान रैली में 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं से वोट चोरी के मुद्दे पर आंदोलन के अगले कदम की घोषणा की उम्मीद थी, पर उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं।

रामलीला मैदान से लोकतंत्र की हुंकार

कुमार कृष्णन

दिल्ली का रामलीला मैदान 1 नवंबर 2026 को एक बार फिर भारतीय राजनीति के केंद्र में था। इंडिया गठबंधन की महारैली केवल विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि मतदाता सूची, चुनावी पारदर्शिता, निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर उठे सवालों का राष्ट्रीय मंच भी थी। वोट बचाओ, देश बचाओ के नारे के साथ आयोजित इस रैली में उमड़ी भीड़ ने यह संकेत दिया कि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विवाद को संसद और राजनीतिक बयानबाजी से आगे ले जाकर जनांदोलन का रूप देना चाहता है।

रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव सहित विभिन्न राज्यों के नेताओं की मौजूदगी ने इसे व्यापक राजनीतिक स्वरूप दिया। अलग-अलग विचारधाराओं और क्षेत्रीय हितों वाले दलों का एक मंच पर आना अपने आप में महत्वपूर्ण था। इस आयोजन में बिहार कांग्रेस के नेताओं और पिछड़ा वर्ग विभाग के पदाधिकारियों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही।

रैली की प्रमुख तस्वीर राहुल गांधी की रही। भारी भीड़ के कारण पदयात्रा के बजाय वे खुले वाहन से रामलीला मैदान पहुंचे। उनके साथ प्रियंका गांधी और दूसरे विपक्षी नेता भी थे। सड़कों पर उमड़े कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच खुले वाहन से नेताओं का आगे बढ़ना जनसंपर्क और शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बना।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर तीखा हमला किया। उनका आरोप था कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों के माध्यम से लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। राहुल गांधी का कहना था कि यदि योग्य नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाते हैं तो चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। उनके भाषण का राजनीतिक संदेश स्पष्ट था। कांग्रेस इस मुद्दे को केवल निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे संविधान, नागरिक अधिकार और सत्ता की जवाबदेही से जोड़ रही है। हालांकि विपक्ष के आरोपों को प्रमाणित तथ्य मानने के बजाय उनकी स्वतंत्र जांच और आयोग के जवाब के संदर्भ में देखना जरूरी है।

इस महारैली का एक अलग और आकर्षक



दृश्य पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव (राजेश रंजन) का तिरंगा मार्च रहा। वे हजारों साधु-संतों और समर्थकों के साथ रामलीला मैदान पहुंचे। हिमाचल भवन और कनॉट प्लेस से मिंटो ब्रिज होते हुए आगे बढ़े इस काफिले में साधु-संतों और कार्यकर्ताओं के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा था।

पप्पू यादव ने आंदोलन को लोकतंत्र, संविधान और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा से जोड़ते हुए केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखे राजनीतिक हमले किए। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी एक राजनीतिक दल या व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और आम लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए है। इस मार्च का महत्व केवल उसमें शामिल लोगों की संख्या में नहीं था। साधु-संतों की भागीदारी ने राजनीतिक विरोध को व्यापक सामाजिक स्वरूप देने का प्रयास किया। भारतीय राजनीति में धार्मिक-सामाजिक समूहों की सार्वजनिक भागीदारी का अपना इतिहास है। इस अवसर पर तिरंगा लेकर उनका मताधिकार और संविधान से जुड़े सवालों पर मार्च करना एक अलग संदेश दे रहा था। पप्पू यादव की इस पहल ने रैली में सामाजिक भागीदारी का एक नया पक्ष जोड़ा।

रामलीला मैदान की महारैली के संदर्भ में बिहार कांग्रेस की भागीदारी को विशेष महत्व देना चाहिए। बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व और राजनीतिक हिस्सेदारी हमेशा महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं। ऐसे में बिहार प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी विभाग के पदाधिकारियों की सक्रियता को केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम में भागीदारी के रूप में नहीं देखा जा सकता। बिहार प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग की उपाध्यक्ष सोनी कुमारी, विभाग के अध्यक्ष अनुराग चंदन और मुंगेर जिला कांग्रेस कमेटी के ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष राकेश कुमार मंडल की भूमिका इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। इन पदाधिकारियों के सामने चुनौती है कि राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जा रहे लोकतांत्रिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के सवालों को बिहार के गांवों, कस्बों और जिला मुख्यालयों तक पहुंचाएं। सोनी कुमारी की भूमिका महिला प्रतिनिधित्व के सवाल से भी जुड़ती है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के सामने शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी की अनेक चुनौतियां हैं। संगठन में महिलाओं की मौजूदगी तभी सार्थक होगी जब उन्हें निर्णय लेने और जनसंपर्क अभियान संचालित करने में वास्तविक भूमिका मिले। राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व केवल पदों की संख्या नहीं, बल्कि नेतृत्व और अधिकार की भागीदारी भी है।

अनुराग चंदन के नेतृत्व में ओबीसी विभाग के सामने सामाजिक न्याय के मुद्दों को व्यापक राजनीतिक कार्यक्रम से जोड़ने की जिम्मेदारी है। जातीय जनगणना, आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसरों की समानता जैसे प्रश्नों पर संगठन को लगातार संवाद करना होगा। मतदाता सूची में किसी योग्य नागरिक का नाम छूटना भी सामाजिक न्याय से जुड़ा सवाल है, क्योंकि मताधिकार नागरिक की राजनीतिक पहचान और भागीदारी का आधार है।

मुंगेर जिला कांग्रेस कमेटी के ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष राकेश कुमार मंडल की जिम्मेदारी भी इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मंचों पर उठे सवालों को स्थानीय स्तर तक ले जाना जिला संगठनों का काम है। मतदाता सूची में नामों की जांच, नए मतदाताओं का पंजीकरण और नाम हटाए जाने से संबंधित शिकायतों में नागरिकों की सहायता जैसे कामों से ही यह अभियान व्यावहारिक रूप ले सकता है।

बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के नेतृत्व में प्रदेश संगठन के सामने भी यही चुनौती है। संगठनात्मक विस्तार के साथ पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महिला और युवा वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। बिहार कांग्रेस को गठबंधन की राजनीति के साथ अपनी स्वतंत्र संगठनात्मक पहचान और जमीनी सक्रियता भी मजबूत करनी होगी।

रामलीला मैदान की रैली की विशेषता विभिन्न राज्यों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं की भागीदारी थी। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, बिहार से तेजस्वी यादव, झारखंड से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, जम्मू-कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला तथा महबूबा मुफ्ती और दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों से आए नेताओं ने इस आयोजन को राष्ट्रीय स्वरूप दिया। वामपंथी दलों की मौजूदगी ने भी विपक्षी एकजुटता को व्यापक बनाया। इस भागीदारी के पीछे अलग-अलग राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियां हैं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर तृणमूल कांग्रेस की आशंकाएं हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने नाम हटाए जाने के सवाल उठाए हैं। बिहार में भी मतदाता अधिकार और चुनावी पारदर्शिता का मुद्दा राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है। झारखंड सहित दूसरे राज्यों के नेताओं ने भी इस प्रश्न को लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़ा।

अखिलेश यादव ने अपने भाषण में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे को उठाया। तेजस्वी यादव ने इसे मतदाताओं के अधिकारों की लड़ाई बताया। ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इस तरह अलग-अलग प्रदेशों की राजनीतिक चिंताएं एक साझा मंच पर सामने आईं।

हालांकि विपक्षी एकता की वास्तविक परीक्षा मंच साझा करने के बाद शुरू होती है। राज्यों में इन दलों के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। सीटों का बंटवारा, नेतृत्व और साझा चुनावी रणनीति जैसे सवाल अभी भी मौजूद हैं। यदि यह एकता केवल केंद्र सरकार के विरोध तक सीमित रहती है तो उसका स्थायित्व कठिन होगा। उसे रोजगार, महंगाई, सामाजिक न्याय और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही जैसे मुद्दों पर भी साझा कार्यक्रम बनाना होगा।

रैली का केंद्रीय मुद्दा विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का आरोप था। विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है और बड़ी संख्या में योग्य मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं।

विपक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई। उसका आरोप है कि निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल हैं। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग का तर्क है कि मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए मृत, दोहरे और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाना आवश्यक है। दोनों पक्षों के दावों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। यदि किसी योग्य नागरिक का नाम गलती से हटाया गया है तो उसे नाम वापस जुड़वाने की सरल प्रक्रिया मिलनी चाहिए। आयोग को राज्यवार आंकड़े, नाम हटाने के कारण और शिकायतों के निपटारे की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय



22. नागार्जुन का शून्यवाद

गतांक से आगे...

उसने बताया था कि न तो यह सम्भव है कि कार्य अपने से ही (अर्थात् अपनी पहिली अवस्था. से) उत्पन्न होता हो जैसा कि सांख्य मानता है क्योंकि उस के अनुसार तन्तु पट की ही पहिली अवस्था है; और न यही सम्भव है कि कार्य दूसरी वस्तु से उत्पन्न होता हो जैसा कि न्याय-वैशेषिक मानता है क्योंकि उस के अनुसार पट से तन्तु भिन्न वस्तु है।

पुराने बौद्ध दर्शन ने इस प्रकार यह दिखा कर कारण से कार्य का बनना सम्भव नहीं, प्रतीत्य-समुत्पाद की स्थापना की थी जिस के अनुसार कारणों के होने पर कार्य होता है; परन्तु कारणों से उत्पन्न नहीं होता। परन्तु शून्यवाद के रूप में हुयी नवीन दार्शनिक क्रान्ति ने प्रतीत्यसमुत्पाद को एक पग आगे बढ़ाया। ऐसा होने पर (कारण के होने पर) यह (कार्य) उत्पन्न होता है, इस का अर्थ यह है कि प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर सापेक्ष है अर्थात् उसका स्वभाव या स्वरूप या सत्त्त्र दूसरी पर अपेक्षित है। उस वस्तु का. अपना स्वभाव या सत्त्व कुछ भी नहीं, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु दूसरी पर सापेक्ष होने के कारण नि:स्वभाव स्वरूपशून्य अथवा शून्य है।

शून्यवाद के अनुसार प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थ है वस्तुओं की परस्पर सापेक्षता (relativity)= नि:स्वभावता अर्थात् शून्यता। और इस सापेक्षता के सिद्धान्त से हीनयान युग में मूल तत्त्वों (primary elements) के रूप में माने हुये धर्म भी बचे नहीं रहे। अर्थात् वे धर्म भी नि:स्वभाव और शून्य माने गये।

शून्यवाद 'Nihilism' नहीं- प्रश्न यह होता है कि वस्तु तत्त्व का सर्वथा लोप करके सम्पूर्ण विश्व को नि:स्वभाव और शून्य रूप से स्थापित करने वाला यह सिद्धान्त क्या सर्वथा निषेधवाद (Nihilism) के रूप में है?

क्रमश:...

वासुदेव बलवंत फड़के

निशा डागर

अगर बात करे भारतीय स्वतंत्रता की क्रांति और उन क्रांतिकारियों की जिनकी वजह से देश को आजादी मिली तो इतिहास की रेत में शायद हज़ारों नाम दबे मिले। पर हम सिर्फ कुछ नामों से ही रु-ब-रु हुए हैं। वैसे तो भारत माँ के इन सभी सपूतों के बारे में जानकारी सहेजने की कोशिश जारी है ताकि आने वाली हर पीढ़ी इनके बलिदान को जान-समझ सके।

ऐसा ही एक महान क्रांतिकारी और भारत माँ का सच्चा बेटा था वासुदेव बलवंत फड़के! फड़के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले भारत के प्रथम क्रान्तिकारी थे। उनका जन्म 4 नवंबर, 1845 को महाराष्ट्र के रायगड जिले के शिरढोणे गांव में हुआ था।

साल 1857 की क्रांति की विफलता के बाद एक बार फिर भारतीयों में संघर्ष की चिंगारी फड़के ने ही जलाई थी।



वासुदेव बलवन्त फड़के बचपन से ही बड़े तेजस्वी और बहादुर बालक थे। उन्हें वनों और पर्वतों में घूमने का बड़ा शौक़ था। कल्याण और पुणे में उनकी शिक्षा पूरी हुई। फड़के के पिता चाहते थे कि वह एक व्यापारी की दुकान पर दस रुपए मासिक वेतन की नौकरी कर लें। लेकिन फड़के ने यह बात नहीं मानी और मुम्बई आ गए।

देश में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर उन्होंने भी ब्रिटिश राज के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें देशी राज्यों से कोई सहायता नहीं मिली तो फड़के ने शिवाजी का मार्ग अपनाकर आदिवासियों की सेना संगठित करने की कोशिश शुरू की।

साल 1879 में उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम-घूमकर नवयुवकों से विचार-विमर्श किया, और उन्हें संगठित करने का प्रयास किया। महाराष्ट्र की कोळी, भील तथा धांगड जातियों को एकत्र कर उन्होने रामोशी नाम का क्रान्तिकारी संगठन खड़ा किया। अपने इस मुक्ति संग्राम के लिए धन एकत्र करने के लिए उन्होने धनी अंग्रेज साहुकारों को लूटा।

महाराष्ट्र के सात ज़िलों में वासुदेव फड़के की सेना का ज़बर्दस्त प्रभाव फैल चुका था। जिससे अंग्रेज़ अफ़सर डर गए थे। इस कारण एक दिन बातचीत करने के लिए वे विश्राम बाग़ में इकट्ठा हुए। वहाँ पर एक सरकारी भवन में बैठक चल रही थी।

13 मई, 1879 को रात 12 बजे वासुदेव बलवन्त फड़के अपने साथियों सहित वहाँ आ गए। अंग्रेज़ अफ़सरों को मारा तथा भवन को आग लगा दी। उसके बाद अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें ज़िन्दा या मुर्दा पकड़ने पर पचास हज़ार रुपए का इनाम घोषित किया। किन्तु दूसरे ही दिन मुम्बई नगर में वासुदेव के हस्ताक्षर से इश्तहार लगा दिए गए कि जो अंग्रेज़ अफ़सर रिचर्ड का सिर काटकर लाएगा, उसे 75 हज़ार रुपए का इनाम दिया जाएगा। अंग्रेज़ अफ़सर इससे और भी बौखला गए।

फड़के की सेना और अंग्रेजी सेना में कई बार मुठभेड़ हुई, पर उन्होंने अंग्रेजी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फड़के की सेना का गोला-बारूद धीरे-धीरे खत्म होने लगा। ऐसे में उन्होंने कुछ समय शांत रहने में ही समझदारी मानी और वे पुणे के पास के आदिवासी इलाकों में छिप गये।

न बहुमत मिला, न सत्ता से बाहर हुए नेतन्याहू!

शेखर गुप्ता

करीब एक दशक पुराने दोस्तों डॉनल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी उदारवादियों और वामपंथियों के नफरत करने वाले लोगों की सूची में शीर्ष स्थान पर कब्जा कर रखा है। उनके राजनीतिक पराभव की कामना की जाती रही है लेकिन दोनों अपने विरोधियों को निराश करते रहे हैं। ट्रंप दो बार राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने उदारवादियों के मखौल और उनकी अवज्ञा को धता बताया। नेतन्याहू 2021-22 की एक साल की नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड की बाधा को छोड़ विगत 17 में से 16 सालों से सत्ता में रहे हैं।

इस बार उन्हें जनादेश नहीं मिला लेकिन उन्होंने सबसे अधिक सीटें हासिल कीं, उन्हें धुर दक्षिणपंथ का समर्थन हासिल है। वह गठबंधन बनाने की हालत में हैं और वह एक नए चुनाव का माहौल भी बना सकते हैं जो इजरायल के लिए नया नहीं है। इसे केवल इसलिए नेतन्याहू की जीत कहा जाएगा क्योंकि उन्हें हराया नहीं गया। उन्होंने हमास की 'मदद' से इजरायल को बुनियादी रूप से बदल दिया है। किसी अन्य परिस्थिति में संभव था कि गादी आइजेनकोट अपने गठबंधन को 48 सीटों से बढ़ाकर बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों से आगे ले जा सकते थे। इसके लिए बस उन्हें दोनों अरब पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ता। इनमें से एक पार्टी, रा'म 2021-22 में नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड के अल्पकालिक गठबंधन में शामिल हुई भी थी।

लेकिन अब कोई भी यहूदी राजनीतिक दल अरब पार्टियों को तब तक अपने साथ नहीं ले सकता जब तक वे हमास को आतंकी संगठन घोषित न करें। अरब पार्टियां ऐसा नहीं करेंगी इसलिए इजरायल के अरब नागरिकों को बाहर रखकर ही कोई गठबंधन बन सकेगा। इस तरह नेतन्याहू और हमास ने इजरायल को बदल दिया है। अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट कुछ हद तक राजनीतिक संतुलन बहाल कर सकते हैं लेकिन वह हकीकत नहीं बदलेगी जिसने ट्रंप को लगभग



असीमित सत्ता तक पहुंचाया। आव्रजन, व्यापार और मानवाधिकारों के मामले में उनका प्रभाव उनके सत्ता से हटने के बाद भी लंबे समय तक बना रहेगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि मतदाता भावनाओं से प्रभावित होते हैं लेकिन उनके फैसले तर्कसंगत भी होते हैं। अर्थव्यवस्था महत्त्वपूर्ण है, लेकिन तीन चीजें उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं-राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा और पहचान का संरक्षण।

ट्रंप ने दूसरा चुनाव कानून-व्यवस्था, आव्रजन और उनके शब्दों में 'सबसे ऊपर' राजनीतिक शुद्धता के मुद्दे पर केंद्रित किया। इसमें अकादमिक जगत में विविधता, समानता और समावेशन (डीईआई) को लेकर बढ़ती बहस, लैंगिक पहचान की तरलता और खुली सीमाओं जैसे मुद्दे शामिल थे। इजरायल का चुनाव राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित था। इजरायलियों के लिए 7 अक्टूबर 2023 का दिन होलोकॉस्ट के बाद का सबसे भयावह अनुभव था। इस घटना ने इजरायल को बदल दिया और बाद में शुरू हुए युद्धों के लिए जनसमर्थन तैयार किया और नेतन्याहू को सत्ता विरोधी लहर से बचाए रखा।

भारत सहित लोकतांत्रिक देशों में उदारवादी विमर्श में प्रचलित रूढ़ धारणाओं के विपरीत इजरायल में गहरी बहस और लोकतांत्रिक परंपरा मौजूद है। वहां उदारवादी और मुखर मतदाताओं का एक मजबूत वर्ग है जो फिलिस्तीनियों के प्रति सहानुभूति रखता है। पश्चिमी किनारे में बस्तियों के निवासियों की हिंसा का विरोध करता है और यहां तक कि दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन भी करता है। मैंने दशकों से हारेत्ज नामक इजरायली अखबार की सदस्यता ले रखी है। यह भारत के किसी भी मुख्यधारा के अखबार की तुलना में कहीं अधिक वामपंथी रुख रखता है। वह नेतन्याहू की आलोचना करता है और उसने ऐसी खबरों का खुलासा किया है जिनसे राजनीतिक रूप से उन्हें भारी नुकसान पहुंचना चाहिए था। इनमें यह खबर भी शामिल है कि 7 अक्टूबर से पहले उन्होंने मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात की चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। यह आरोप भी लगाया जाता रहा है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया।

दूसरी ओर अति-रूढ़िवादी यहूदी राजनीतिक दल हैं जो पश्चिमी किनारे और गाजा से सभी फिलिस्तीनियों को बेदखल करना चाहते हैं। इजरायली समाज में गहरे मतभेद हैं और वहां अंधभक्ति की परंपरा नहीं है। लेकिन ये विभाजन चुनाव में दिखाई नहीं दिए। यहूदियों ने दो कट्टरपंथी नेताओं में से एक को चुना। 21 फीसदी अरब अल्पसंख्यक वर्ग को आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली चुनाव प्रणाली में सीटें तो मिलती हैं लेकिन अंतत: उनके वोटों का कोई खास महत्त्व नहीं रह जाता क्योंकि सुरक्षा और अस्तित्व के सवाल पर बहुमत एकजुट हो जाता है। नेतन्याहू ने ही जनरल गादी आइजेनकोट को इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) का प्रमुख नियुक्त किया था। आइजेनकोट के सैनिक बेटे की गाजा में लड़ते हुए मौत हो गई और वे भी हमास का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पर्याप्त संख्या में मतदाताओं ने बदलाव का जोखिम उठाने के बजाय निरंतरता को चुना। यहां विचार करने की जरूरत है कि कभी इजरायल में ताकतवर रहा वामपंथ अचानक कब और क्यों अप्रासंगिक हो गया? और दूसरा, वहां के अरब नागरिकों के भारी चुनावी समर्थन का कोई महत्त्व क्यों नहीं रह गया?

इजरायल में वामपंथ (लेबर) के वर्चस्व का दौर भारत में बहुत अधिक याद नहीं किया जाता। डेविड बेन-गुरियन, गोल्डा मायर, लेवी एश्कोल और यित्जाक राबिन आधुनिक इजरायल के महानतम जायोनी नेता और संस्थापक सभी लेबर पार्टी से थे। दिग्गज लेफ्टिनेंट जनरल मोशे दयान लेबर के समाजवादी और स्वयं को जायोनी नास्तिक घोषित करने वाले नेता थे। 1977 में उन्होंने लेबर छोड़कर मेनाखेम बेगिन के लिकुड गठबंधन का समर्थन किया और विदेश मंत्री के रूप में मिस्र के साथ शांति के लिए कैंप डेविड समझौते पर बातचीत की।

1948 से 1977 तक इजरायल की राजनीति में लेबर का पूरी तरह वर्चस्व रहा। बेगिन की लिकुड पार्टी ने इसे तोड़ा। इसके बाद शिमोन पेरेज, राबिन और एहुद बराक के नेतृत्व में लेबर को 1984, 1992, 1995 और 1999 में कुछ समय के लिए सत्ता में वापसी का मौका मिला लेकिन इसके बाद उसका प्रभाव धीरे-धीरे खत्म होता चला गया।

1992 से 2000 के बीच लेबर पार्टी ने ओस्लो समझौते के तहत बातचीत के जरिए मिस्र की तर्ज पर शांति स्थापित करने की कोशिश की लेकिन यह प्रयास विफल रहा। इस दौरान फिलिस्तीनी हमले और आत्मघाती बम विस्फोट बढ़ते गए। पहली बार यह प्रक्रिया राबिन की हत्या के साथ समाप्त हुई और फिर 2000 में दूसरा इंतिफादा (फिलिस्तीनी विद्रोह) शुरू होने की स्थिति बन गई। आखिरकार इजरायलियों को लेबर की 'शांति के बदले जमीन' की अवधारणा अव्यावहारिक और दिशाहीन लगी। तब से इजरायल में शांति के नाम पर वोट मांगना लगभग असंभव हो गया है। विडंबना यह है कि भारत सहित दुनिया के अधिकांश देश दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन करते हैं लेकिन इस संघर्ष के दोनों प्रत्यक्ष पक्षों में से कोई भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। अरब मतों का महत्त्व इतना नगण्य होने पर भी हमें गंभीरता से अध्ययन करने की जरूरत है क्योंकि हाल के दिनों में भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था अपनाने की मांग उठी है। माना जाता है कि इससे अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी आबादी के अनुपात में सीटें मिल सकेंगी। इजरायल का अनुभव इस धारणा की एक कठोर वास्तविकता से सामना कराता है। वहां मुख्य रूप से मुस्लिम अरब समुदाय की आबादी इजरायल की कुल आबादी के 20 फीसदी से अधिक है।

आज का इतिहास

1509 अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में दूसरे पुर्तग़ाली वायसराय बने।
1619 फ्रेडरिक पंचम यूरोपीय देश बोहेमिया के राजा बने।
1822 दिल्ली में जल आपूर्ति योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ।
1856 जेम्स बुकानन अमेरिका के 15वें राष्ट्रपति बने।
1875 अमेरिका के बोस्टन में मैसाचुसेट्स राइफल एसोसिएशन की स्थापना हुयी।
1911 अफ्रीकी देश मोरक्को और कांगो को लेकर फ्रांस तथा जर्मनी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर।
1956 हंगरी में बगावत को कुचलने के लिए सोवियत सेनाएं वहां पहुंची।
1979 ईरान में बंधक संकट की शुरूआत। तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर ईरान के उग्रवादियों ने हमला कर वहां मौजूद लोगों को बंधक बनाया।
1984 ओ बी अग्रवाल एमेच्योर स्नूकर के विश्व चैंपियन बने।
1997 सियाचीन बेस कैम्प में सेना की आफ़ सिग्नल ने विश्व का सर्वाधिक ऊँचा एस.टी.डी. बूथ स्थापित किया।
2000 संयुक्त राष्ट्र संघ में परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने व विखंडनीय पदार्थों के उत्पादन पर रोक संबंधी जापान का प्रस्ताव भारत के विरोध के बावजूद पारित।
2002 चीन ने आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र संधि पर हस्ताक्षर किये।
2003 श्रीलंका की राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा ने रक्षा, गृह और सूचना मंत्रियों को बर्खास्त कर संसद को निलम्बित किया।
2005 संयुक्त राष्ट्र की ईराक के लिए तेल के बदले खाद्यान्न योजना में की गई गड़बड़ी की जाँच की रिपोर्ट तैयार करने वाले पॉल वोल्कर ने स्पष्ट किया कि आरोपियों को सफाई का अवसर दिया गया था।
2008 सार्वजनिक क्षेत्र के छह बैंक बेंचमार्क उधारी दर में 0.75 के आधार अंक तक की कटौती करने पर सहमत हुई। केन्द्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने का निर्णय लिया। चन्द्रमा के लिए भारत का पहला मानवरहित अंतरिक्षयान चन्द्रयान-1 चन्द्रमा के अंतरिक्ष कक्ष में पहुँचा।
2008 बराक ओबामा अफ्रीकी मूल के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने।
2015 दक्षिणी सूडान के जूबा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के तुरंत बाद एक कार्गो विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 37 लोगों की मौत।
2015 पाकिस्तान के लाहौर में एक इमारत ढ़हने से 45 मरे तथा करीब 100 लोग घायल हुए।

नागपुर और वाराणसी में भाजपा की करार हार से सत्ता पक्ष की नींद उड़ी

नीरज कुमार दुबे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही सोशल मीडिया पर कांग्रेस की सीटों की संख्या को लेकर तंज कसते हुए पूछा कि आखिर कांग्रेस को कितनी सीटें मिलीं, उसके कुछ ही समय बाद महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर अपना खाता खोल दिया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी भाजपा को दोनों विधान परिषद सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और विपक्षी समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। इस तरह कांग्रेस पर कटाक्ष करने की कोशिश में भाजपा खुद ही राजनीतिक कटाक्ष का निशाना बन गई। आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में कांग्रेस की जीत और मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विपक्ष की सफलता ने इन एमएलसी चुनावों के नतीजों को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया।

देखा जाये तो चार राज्यों के विधान परिषद चुनावों के नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीति में एक दिलचस्प तस्वीर पेश की है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने कुल 28 सीटों में 16 पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को केवल महाराष्ट्र की नागपुर स्नातक सीट पर सफलता मिली। लेकिन इन परिणामों का राजनीतिक महत्व केवल सीटों के कुल आंकड़े तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र में नागपुर और उत्तर प्रदेश में वाराणसी की हार ने भाजपा के लिए प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उसके संगठनात्मक प्रभाव पर चर्चा शुरू कर दी है।

हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र की नागपुर स्नातक निर्वाचन सीट पर कांग्रेस के अभिजीत वंजारी ने भाजपा के सुधाकर कोहले को 3,271 मतों से हराकर सीट बरकरार रखी। वंजारी को 67,231 और कोहले को 63,960 वोट मिले। लगभग दो दिन चली मतगणना में दूसरे वरीयता के मत निर्णायक साबित हुए। इस निर्वाचन क्षेत्र का महत्व इसलिए भी है कि नागपुर आरएसएस का मुख्यालय होने के साथ-साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गृहक्षेत्र भी है। यह परिणाम भाजपा के लिए स्थानीय स्तर पर संगठन और मतदाता संपर्क की समीक्षा का अवसर है। गडकरी लंबे समय तक इसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और भाजपा ने इस बार भी सीट वापस पाने के लिए अभियान चलाया था। इसके बावजूद कांग्रेस की लगातार दूसरी जीत बताती है कि मजबूत वैचारिक और संगठनात्मक आधार वाले क्षेत्र में भी चुनावी परिणाम स्वत: सुनिश्चित नहीं होते।

दूसरी ओर, कांग्रेस ने इस जीत को भाजपा के शुरुआती दावों के जवाब के रूप में पेश किया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मुख्यमंत्री फडणवीस की उस सोशल मीडिया पोस्ट पर तंज कसा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के शून्य सीटों पर रहने की बात कही थी। नागपुर का परिणाम आने के बाद पार्टी ने उनकी पोस्ट हटाए जाने को लेकर भी कटाक्ष किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इसे भाजपा के राजनीतिक दावों के लिए झटका बताया।



वहीं उत्तर प्रदेश के चुनावों में वाराणसी का परिणाम और भी महत्वपूर्ण रहा। समाजवादी पार्टी ने वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में लाल बिहारी यादव के माध्यम से अपनी सीट बरकरार रखी। इसके साथ ही सपा के आशुतोष सिन्हा ने वाराणसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी जीत हासिल की। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से जुड़ी दोनों विधान परिषद सीटें भाजपा के हाथ से निकल गईं। पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 11 में से छह और सपा ने पांच सीटें जीतीं।

वैसे इन नतीजों का अर्थ यह नहीं है कि वाराणसी के सभी मतदाताओं ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया है। विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों का मतदाता वर्ग सीमित और विशिष्ट है। फिर भी, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले वाराणसी में दोनों सीटों पर हार सपा के लिए राजनीतिक उत्साह बढ़ाने वाली और भाजपा के लिए स्थानीय संगठन की समीक्षा करने वाली घटना है।

हम आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने एमएलसी चुनावों में कांग्रेस के शुरुआती कमजोर प्रदर्शन पर तंज कसा था। इसके जवाब में कांग्रेस नेताओं ने नागपुर और वाराणसी के परिणामों को सामने रखकर भाजपा पर पलटवार किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस की सीटों की संख्या पर टिप्पणी करने के साथ यह भी आत्ममंथन करना चाहिए कि वाराणसी में भाजपा दोनों सीटें क्यों हार गई और आरएसएस के गढ़ नागपुर में कांग्रेस ने जीत कैसे हासिल की? उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और निजी निवेश से जुड़े मुद्दों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि मतदाताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति असंतोष जताया है।

वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी प्रधानमंत्री की बैलेट पेपर वाली टिप्पणी पर पलटवार करते हुए नागपुर और वाराणसी के परिणामों का उल्लेख किया। उनका तर्क था कि यदि भाजपा बैलेट पेपर से हुए चुनावों के नतीजों को कांग्रेस की कमजोरी का प्रमाण बता रही है, तो उसे अपने उन क्षेत्रों में हार पर भी जवाब देना चाहिए जहां भाजपा की मजबूत राजनीतिक मौजूदगी मानी जाती है।

दूसरी ओर, समग्र तस्वीर में एनडीए की 16 सीटों की जीत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में भाजपा-जेडीएस गठबंधन ने चारों सीटें जीतीं, उत्तर प्रदेश में भाजपा छह सीटों पर विजयी रही और बिहार में भाजपा-जदयू ने मिलकर चार सीटें हासिल कीं। दूसरी ओर, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने पांच में से तीन सीटें जीतीं और उत्तर प्रदेश में सपा ने पांच सीटों पर सफलता हासिल की।

इन परिणामों से तीन राजनीतिक संदेश निकलते हैं। एक तो एनडीए का कुल प्रदर्शन उसे मनोवैज्ञानिक बढ़त देता है। दूसरा, नागपुर और वाराणसी जैसे प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हार भाजपा के लिए स्थानीय चुनावी समीकरणों और संगठनात्मक रणनीति की समीक्षा का विषय है। तीसरा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ समन्वय और चुनावी प्रदर्शन को मजबूत करना जरूरी है।

बहरहाल, नागपुर और वाराणसी में भाजपा की हार को महज स्थानीय चुनावी घटनाक्रम बताकर खारिज नहीं किया जा सकता। एक ओर एनडीए ने कुल सीटों के आंकड़े में बढ़त बनाकर अपनी चुनावी ताकत का प्रदर्शन किया, तो दूसरी ओर विपक्ष ने उन क्षेत्रों में भाजपा को शिकस्त दी, जिनकी पहचान उसके मजबूत राजनीतिक प्रभाव से जुड़ी है। आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में कांग्रेस की जीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी की सफलता ने भाजपा के राजनीतिक दावों के बीच असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें आगामी विधानसभा चुनावों पर हैं, देखना होगा कि क्या विपक्ष इन प्रतीकात्मक जीतों को व्यापक जनसमर्थन में बदलकर भाजपा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर पाएगा, या भाजपा इन झटकों से सबक लेकर अपने गढ़ों में फिर पकड़ मजबूत करेगी?

नतीजे तय करेंगे दुनिया की दिशा, ट्रंप का शेष कार्यकाल कैसा बीतेगा?

महेंद्र वेद

अमेरिका के लाखों मतदाताओं ने मध्यावधि चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इन चुनावों के नतीजे न केवल ट्रंप प्रशासन के बाकी दो वर्षों की राजनीतिक दिशा करने वाले हैं, बल्कि दुनिया को प्रभावित कर रहे दो युद्धों के भविष्य पर भी असर डाल सकते हैं। वैश्विक समुदायज्ञ अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक इस पर नजर रख रहे हैं कि अगर ट्रंप कांग्रेस या प्रतिनिधि सभा या दोनों पर अपना नियंत्रण खो देते हैं, तो अमेरिका के बाहर इसके क्या आर्थिक और सैन्य प्रभाव पड़ सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि विपक्षी डेमोक्रेट्स, भले ही भारी जीत हासिल न कर सकें, लेकिन वे चुनाव में आगे रह सकते हैं। प्रतिनिधि सभा जीतने के मामले में उनका पलड़ा भारी है, पर सीनेट की कई कड़े मुकाबले वाली सीटों से यह तय हो सकता है कि कांग्रेस पर किसका नियंत्रण होगा। प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 35 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। हालांकि, ट्रंप यूक्रेन के युद्ध पर कोई असर डालने में नाकाम रहे, लेकिन ईरान का युद्ध उनके प्रति लोगों के समर्थन को पलटने वाला सबसे बड़ा कारक बनकर उभरा है। चुनावों से पहले हुए सर्वे बताते हैं कि उनकी लोकप्रियता काफी घट गई है। ट्रंप की कूटनीति और बल प्रयोग पूरी तरह विफल रही हैं। उनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। मतदान से कुछ घंटे पहले उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध 'बहुत जल्द खत्म हो जाएगा'। उन्होंने चेतावनी दी कि या तो तेहरान कोई समझौता कर ले, वरना 'हम इसे खुद ही खत्म कर देंगे'। लेकिन, ईरान काफी उत्साहित है। उसने घोषणा की कि होर्मुज की खाड़ी में दो और तेल टैंकरों को 'बारूदी सुरंगों से निशाना' बनाया गया है। साथ ही, चेतावनी दी कि अमेरिका के साथ कोई भी नया युद्ध पिछले संघर्ष की तुलना में लंबा खिंच सकता है, और अमेरिकी राष्ट्रपति तय नहीं करेंगे कि यह युद्ध कितने समय तक चलेगा। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, अमेरिका में डीजल की ऊंची कीमतों को काबू में करने के लिए ट्रंप द्वारा रूस से डीजल की खरीद ने पुतिन की स्थिति को मजबूत किया है। इसी तरह, भारत पर ज्यादा से ज्यादा डीजल रिफाइन करने का दबाव डालने से ट्रंप प्रशासन की उस आलोचना की पोल भी खुल गई है, जिसमें कहा गया था कि रूस से तेल खरीदकर भारत, पुतिन के यूक्रेन युद्ध में 'मदद' कर रहा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले हिस्से में दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई हैं और अमेरिका ने अपने दोस्त और सहयोगी खो दिए हैं। अमेरिकी मतदाताओं की तरह, वे भी शायद मध्यावधि चुनावों के नतीजों का ही इंतजार कर रहे हैं। वेनेजुएला का तेल हथियाने के लिए वहां की सत्ता बदलने के लिए दबाव डालना चिंता का विषय बन गया है। इस्राइल में राजनीतिक गतिरोध भी ट्रंप के लिए एक निराशाजनक बात है। हालांकि, पहले भी मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति की पार्टी को अक्सर कांग्रेस की सीटें गंवानी पड़ती थीं। अगर ट्रंप चुनाव हार जाते हैं, तो उनका प्रशासन गतिरोध और कड़ी जांच के घेरे में आ जाएगा। यही नहीं, उन पर महाभियोग चलाने को लेकर एक लंबी विधायी लड़ाई छिड़ने का खतरा है। ट्रंप के विधायी एजेंडे पर असर पड़ेगा, जिससे टैक्स में कटौती और राहत की गुंजाइश सीमित हो जाएगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाली कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों को रोकने के लिए ट्रंप संभवत: अपने राष्ट्रपति के वीटो अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इससे सरकारी खर्च, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर गतिरोध पैदा हो सकता है। ट्रंप संभवत: आव्रजन, व्यापार और ऊर्जा के क्षेत्रों में अपनी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए एकतरफा कार्यकारी आदेशों, नियामक कदमों और प्रशासनिक उपायों पर अधिक निर्भर रहेंगे।

लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने

सनत जैन

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह एक असाधारण राजनीतिक स्थिति है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोकतंत्र बचाने का नारा लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को इंडिया गठबंधन की वोट बचाओ, देश बचाओ रैली और इसके जवाब में भाजपा का देशव्यापी लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान इस बात का संकेत है। चुनावी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक संघर्ष अब संसद की सीमाओं से बाहर निकलकर सड़कों तक पहुंच गया है।

इंडिया गठबंधन की रैली की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राजद, वामपंथी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं के नाम काटने तथा चुनाव के दौरान कंप्यूटर की सहायता से भारी हेरफेर किए जाने के आरोप मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए और सवाल उठाए गए। इस आयोजन में राजनीतिक नेताओं के साथ सामाजिक संगठनों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों, युवाओं और उन मतदाताओं ने भी भागीदारी की, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गये थे।

31 अक्टूबर को आयोजित प्रतीकात्मक जन संसद में भी विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ छह आरोपों के साथ प्रस्ताव पारित किया। विपक्ष की मांग है, ज्ञानेश कुमार को पद से हटाया जाये। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच हो। इस पूरे



विवाद की जड़ एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल के अनुसार 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रारूप मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए। सबसे गंभीर बात यह है कि चुनाव आयोग के ही दो अन्य आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कई बार आयोग के भीतर प्रक्रियाओं और फैसलों पर लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं। अखबार की रिपोर्ट में ऐसी 14 आपत्तियों का उल्लेख है। इससे चुनाव आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। ज्ञानेश कुमार एक तरफा फैसला ले रहे थे।

राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में अपने भाषण के दौरान ज्ञानेश कुमार और चुनावी प्रक्रिया को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी में शामिल लोगों को जवाबदेह बनाया जाएगा। ममता बनर्जी ने भी बताया पश्चिम बंगाल का चुनाव किस तरह लूटा गया है, डकैती डाली गई है। रैली में वक्ताओं ने बड़े आक्रामक तरीके से चुनाव आयोग द्वारा की गई गडबड़ियों का उल्लेख किया। दूसरी ओर भाजपा ने विपक्ष के आंदोलन को अराजकता फैलाने की कोशिश बताते हुए देशभर में जवाबी कार्यक्रम आयोजित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के समर्थन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अलग-अलग राज्यों में पदयात्राओं और सभाओं के माध्यम से विपक्ष के ऊपर हमला किया है।

यह भी सत्य है कि इस बार विपक्ष के साथ भारी भीड़ है, जनमानस का समर्थन प्राप्त है। उसके मुकाबले में भाजपा की पदयात्रा और रैली में वह भीड़ देखने को नहीं मिली जो होना चाहिए थी। यह राजनीतिक संघर्ष अब केवल राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी अथवा कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं रह गया है। इसका सीधा संबंध देश की संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से जुड़ गया है। चुनाव आयोग पर आरोप लगना और उन आरोपों का राजनीतिक रूप से जवाब देना, अलग बात है। आयोग की निष्पक्षता पर आम जनता और राजनीतिक दलों का भरोसा बना रहना अनिवार्य है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है।

आरोपों का अंतिम निर्णय तथ्यों, जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा। विपक्ष ज्ञानेश कुमार की स्थिति को लेकर जो दबाव बना रही है, सत्ता पक्ष के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। उल्टे सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है, देश पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक सुस्ती, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मे बढ़ता टकराव सरकार के विकास कार्यों एवं जरूरी मुद्दों पर समय पर निर्णय नहीं ले पाने के कारण सरकार की परेशानी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इसका असर अंतोगत्वा जनता पर ही पडना है।

लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी-अपनी भूमिका है। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी उन सवालों का जवाब देना है। चुनाव आयोग को भी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पारदर्शिता के साथ प्रश्नों का जवाब देने के लिए सामने आना चाहिए। यदि विपक्ष के आरोप गलत हैं, तो तथ्यों के साथ चुनाव आयोग द्वारा उन्हें खारिज किया जाना चाहिए। यदि कहीं गड़बड़ी हुई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच और उसमें सुधार होना चाहिए।

चुनाव आयोग को अपनी कार्य प्रणाली इस तरीके से तैयार करनी होगी, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को विश्वास हो। पिछले 7 दशकों में राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग के बीच जो विश्वास बना था वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लोकतंत्र किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। वह 140 करोड़ देशवासियों का साझा अधिकार और विश्वास है। सवाल यह नहीं होना चाहिए, सड़क पर कौन जीता और कौन हारा, बल्कि यह होना चाहिए देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा कैसे कायम रहे। यदि सत्ता और विपक्ष ने राजनीतिक अहंकार से ऊपर उठकर समाधान नहीं खोजा, तो इस टकराव का नुकसान अंतत: देश और आम नागरिकों को ही उठाना पड़ेगा।

क्या 'वोट चोरी' का मुद्दा निर्णायक आंदोलन बन पाएगा?

सत्येंद्र प्रताप सिंह

1 नवंबर को दिल्ली का रामलीला मैदान विपक्षी राजनीति का केंद्र बना। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और वोट चोरी के आरोपों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। इस आयोजन का केंद्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग रही। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और इससे मतदान के अधिकार पर सवाल खड़े हुए हैं। रैली से पहले विपक्ष ने प्रतीकात्मक जन महाभियोग कार्यक्रम भी आयोजित किया था। इसके बाद चलो दिल्ली मार्च के जरिए विपक्षी दल रामलीला मैदान पहुंचे।

इस रैली को लेकर भीड़ का आंकड़ा भी राजनीतिक चर्चा का विषय रहा। कांग्रेस की ओर से 10 लाख लोगों के जुटने की अपेक्षा जताई गई थी, जबकि दिल्ली पुलिस का अनुमान लगभग 50 हजार का बताया गया। मैदान की क्षमता और मौके की परिस्थितियों को देखते हुए वास्तविक भीड़ का आकलन आयोजकों के दावों से अलग किया जाना चाहिए। बड़ी भीड़ जुटना अपने आप में राजनीतिक सफलता का प्रमाण नहीं है। असली सवाल है कि क्या वहां जुटे लोगों की नाराजगी किसी लंबे राजनीतिक अभियान में बदलती है?

इस रैली की एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी दलों और अन्य विपक्षी संगठनों के नेताओं की भागीदारी दिखाई दी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी, फारूक अब्दुल्ला और दूसरे नेताओं की मौजूदगी ने विपक्षी एकजुटता का संदेश दिया। लेकिन यहां

एक बुनियादी सवाल है। क्या एक मंच पर आना और एक साथ चुनाव लड़ना दो अलग-अलग बातें नहीं हैं?

विपक्षी दलों के बीच कई राज्यों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। बंगाल में तृणमूल और कांग्रेस-वामपंथी दलों के बीच मुकाबला है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों और नेतृत्व को लेकर अलग-अलग प्राथमिकताएं हैं। ऐसे में रामलीला मैदान की साझा तस्वीर निश्चित रूप से राजनीतिक संदेश देती है, लेकिन यह अपने आप में भविष्य की चुनावी एकजुटता की गारंटी नहीं है। एकजुटता का असली इम्तिहान मंच पर नहीं, चुनाव के मैदान में होगा।

इस रैली का एक दूसरा राजनीतिक पहलू राहुल गांधी की भूमिका है। कांग्रेस ने इस आयोजन को बड़े स्तर पर तैयार किया। राहुल गांधी ने न केवल रैली में भागीदारी की अपील की, बल्कि मार्च को भी नेतृत्व दिया। पार्टी इसे लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा से जोड़ रही है।

लेकिन विपक्ष के सामने एक चुनौती यह भी है कि क्या गठबंधन के सभी सहयोगी राहुल गांधी को अपना स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता स्वीकार करते हैं?ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और दूसरे क्षेत्रीय नेताओं की अपनी राजनीतिक जमीन और महत्वाकांक्षाएं हैं। वे कांग्रेस के साथ साझा मुद्दों पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे अपने राजनीतिक प्रभाव या नेतृत्व की स्वतंत्रता को छोड़ने के लिए तैयार हैं।

इसलिए इस रैली को राहुल गांधी के नेतृत्व की अंतिम स्वीकृति मानना जल्दबाजी होगी। इसे विपक्षी दलों के बीच साझा मुद्दे पर एक साथ आने के प्रयास के रूप में देखना अधिक उचित होगा।

रैली का केंद्रीय मुद्दा चुनाव आयोग और मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्क्रूक रहा।विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए और पात्र नागरिकों के मतदान के अधिकार प्रभावित हुए। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि पुनरीक्षण का उद्देश्य मृत, स्थानांतरित, दोहरे और अपात्र मतदाताओं के नाम हटाकर सूची को शुद्ध करना है। यहां एक महत्वपूर्ण बात है। मतदाता सूची की शुद्धता और प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदान का अधिकार, दोनों लोकतंत्र के लिए अनिवार्य हैं। इसलिए विपक्ष के आरोपों की निष्पक्ष जांच और चुनाव आयोग की प्रक्रिया में पारदर्शिता, दोनों जरूरी हैं। केवल राजनीतिक भाषणों से इन सवालों का समाधान नहीं होगा। विपक्ष को ठोस उदाहरण, दस्तावेज और प्रमाण भी सार्वजनिक करने होंगे।

यही इस पूरे आयोजन का सबसे बड़ा सवाल है।पिछले कुछ समय से विपक्षी दल लगातार एकजुटता दिखा रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक, राष्ट्रपति से मुलाकात से लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध तक, विपक्ष ने कई स्तरों पर अपनी सक्रियता दिखाई है। लेकिन क्या इस सक्रियता का कोई ठोस परिणाम निकला है?

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग करना एक राजनीतिक मांग है। लेकिन क्या केवल इस्तीफे की मांग से मतदाता सूची से जुड़े विवाद का समाधान हो जाएगा? क्या विपक्ष के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था और ठोस सुधार प्रस्ताव भी है? अगर विपक्ष वास्तव में मताधिकार की रक्षा को लेकर गंभीर है तो उसे कुछ व्यावहारिक मांगें भी सामने रखनी होंगी।

1. मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी हो। 2. प्रभावित मतदाताओं को समय पर सुनवाई का अवसर मिले। 3. राजनीतिक दलों को शिकायतों के निवारण की व्यवस्था मिले। 4. चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठने वाले सवालों का तथ्यात्मक जवाब दिया जाए।

रामलीला मैदान की रैली को केवल मोदी सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह विपक्ष की अपनी राजनीतिक परीक्षा भी है। उसे यह साबित करना होगा कि वह केवल विरोध करने के लिए एकजुट नहीं हुआ है, बल्कि उसके पास लोकतांत्रिक संस्थाओं, चुनाव प्रक्रिया और मतदाता अधिकारों से जुड़े सवालों पर साझा दृष्टिकोण भी है।

विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि रामलीला मैदान की ऊर्जा को देश के अलग-अलग राज्यों में संगठनात्मक सक्रियता में कैसे बदला जाए। सिर्फ दिल्ली में भीड़ जुटाने से राजनीतिक समीकरण नहीं बदलते। इसके लिए राज्यों में साझा रणनीति, स्थानीय नेतृत्व के बीच तालमेल और चुनावी मुद्दों पर सहमति जरूरी है।

रविवार की रैली ने कम से कम यह दिखाया कि विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर एक मंच पर आने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस एकजुटता की उम्र कितनी होगी? क्या यह आंदोलन आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा? क्या सहयोगी दल अपने आपसी मतभेदों को पीछे रख पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस विरोध से कोई संस्थागत या राजनीतिक परिणाम निकलेगा? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा रामलीला मैदान ने विपक्ष को अपनी एकजुटता दिखाने का अवसर दिया है।

डीपफेक के दौर में राजनीति, कहीं विपक्ष दुश्मन का हथियार तो नहीं बन रहा?

विनोद पाठक

पिछले दिनों एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ। पहली नजर में यह वास्तविक प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसमें किए गए दावे और उसकी भाषा संदेह पैदा करने वाले थे। विडंबना यह रही कि वीडियो के फर्जी होने के बावजूद विपक्ष के कुछ नेताओं ने इसे साझा किया। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े किसी वीडियो को बिना सत्यापन प्रसारित करना महज राजनीतिक चूक नहीं, बल्कि देश की सामरिक विश्वसनीयता, सेना के मनोबल और जनविश्वास के लिए गंभीर चुनौती है। लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व सरकार से सवाल पूछना है। चीन की गतिविधियों, सीमाओं की सुरक्षा, सैन्य तैयारियों और सैनिकों को उपलब्ध सुविधाओं पर सवाल उठाना उसका अधिकार है। सरकार की नीतियों में कमी हो तो उसे सामने लाना भी जरूरी है, लेकिन सरकार की आलोचना और अपुष्ट सामग्री को प्रमाण की तरह प्रसारित करना दो अलग बातें हैं। पहली लोकतांत्रिक जवाबदेही का हिस्सा है, जबकि दूसरी सार्वजनिक विमर्श को गलत सूचना की गिरफ्त में ले जा सकती है। समस्या तब गंभीर हो जाती है, जब किसी सूचना की सत्यता से अधिक उसके राजनीतिक उपयोग को महत्व मिलने लगता है। सरकार को कठघरे में खड़ा करने की जल्दबाजी में क्या यह देखना जरूरी नहीं कि वीडियो वास्तविक है या फर्जी? क्या किसी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के नाम से प्रसारित बयान को केवल इसलिए सच मान लिया जाए कि वह राजनीतिक आरोपों को बल देता है? किसी गंभीर आरोप को सार्वजनिक करने से पहले मूल वीडियो, संबंधित अधिकारी का वास्तविक बयान और आधिकारिक स्पष्टीकरण देखना सामान्य सावधानी होनी चाहिए। राजनीतिक दलों के पास संसाधन, शोधकर्ता और संचार तंत्र उपलब्ध हैं। इसलिए उनसे तथ्य-जांच के मामले में अधिक जिम्मेदारी की अपेक्षा स्वाभाविक है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से दुष्प्रचार की आशंकाएं नई नहीं हैं। दोनों देशों के बीच तनाव के दौरान सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे, पुराने वीडियो और कथित सैन्य घटनाओं से जुड़ी झूठी सामग्री प्रसारित होती रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और सरकारी फैक्ट-चेक इकाइयों ने समय-समय पर ऐसी सामग्री का खंडन किया है। डीपफेक तकनीक ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है। अब किसी वास्तविक सैन्य अधिकारी के चेहरे और आवाज का इस्तेमाल करके ऐसा बयान तैयार किया जा सकता है, जो उसने कभी दिया ही नहीं। ऐसे दुष्प्रचार का उद्देश्य केवल झूठी खबर फैलाना नहीं होता। इसके जरिए सेना की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करने और जनता के मन में देश की सैन्य स्थिति को लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा सकती है। यदि ऐसी सामग्री को देश के भीतर प्रभावशाली राजनीतिक आवाजों का सहारा मिल जाए, तो उसकी पहुंच और विश्वसनीयता का भ्रम दोनों बढ़ सकते हैं। विदेशी दुष्प्रचार तंत्र के लिए इससे अनुकूल स्थिति और क्या होगी कि उसके संदेश को आगे बढ़ाने के लिए घरेलू राजनीतिक मंच भी उपलब्ध हो जाए? यहीं विपक्षी नेताओं की भूमिका पर गंभीर सवाल उठते हैं। यदि कोई नेता बिना सत्यापन ऐसी सामग्री साझा करता है, तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह जानबूझकर पाकिस्तान या किसी विदेशी एजेंसी के एजेंडे पर काम कर रहा है। किसी की नीयत पर आरोप लगाने के लिए ठोस प्रमाण चाहिए। लेकिन उसकी राजनीतिक और सार्वजनिक जिम्मेदारी का मूल्यांकन जरूर किया जाना चाहिए। क्या वीडियो साझा करने से पहले उसकी प्रामाणिकता जांची गई थी? यदि नहीं, तो क्या गलती सामने आने पर उसे स्वीकार किया गया? क्या लोगों को बताया गया कि साझा की गई सामग्री भ्रामक निकली? प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों की सोशल मीडिया पर व्यापक पहुंच होती है। उनके एक संदेश को लाखों लोग देख सकते हैं, जबकि उसका खंडन शायद उतने लोगों तक कभी न पहुंचे। इसलिए किसी गलत दावे को साझा करने के बाद केवल पोस्ट हटा देना पर्याप्त नहीं होना चाहिए।



बचे हुए खाने को कभी न करें बर्बाद! अपनाएं ये स्मार्ट किचन हैक्स

ताजा खाना खाने से सेहत भी बढ़िया होती है। लेकिन घर में हर बार नाप-तौल के खाना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बचे हुए खाने को कभी भी बर्बाद न करें, इससे अच्छा है कि लेफ्टओवर का फूड यूज कर सकते हैं। जब आपका खाना बनाने का मन न करें तो इन आसान तरीकों से लेफ्टओवर फूड को का इस्तेमाल कर सकते हैं।

लेफ्टओवर की करें प्लानिंग

कई बार होता है कि बाहर किसी काम से हमें कहीं जाना होता है, तो फिर घर लौटकर खाना बनाने में दिक्कत होती है। ऐसे में आप अपनी मनपसंद रेसिपी ज्यादा मात्रा में तैयार करके रख लें। फिर इसे फ्रिज में स्टोर करके रख दें, अब आपको खाना पकाने की कोई चिंता नहीं होगी। आप चाहे तो चीला या डोसा के लिए ज्यादा बैटर बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं या फिर बिना सिकी हुई पैटी या उबले आलू।

ये चीजें लगती हैं ज्यादा टेस्टी

रात या दोपहर का खाना बच ही जाता है, ऐसे में आप अगली मील की प्लानिंग में बचे हुए खाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीजें दोबारा गर्म करके खाने और पीने में ज्यादा टेस्टी लगती है, जैसे कि सूप, दाल, करी, रोस्ट की गई सब्जियां।

पारदर्शी कंटेनर में स्टोर करें

अक्सर होता है कि हम सभी खाना फ्रिज में रखकर भूल जाते है। इसलिए हमेशा कांच के पारदर्शी लंच बॉक्स या मैसन जार में खाना स्टोर करें। यह आपको फ्रिज खोलते ही नजर आने लगेंगे।

बचे हुए खाना से नई रेसिपी बनाएं

अगर आपका खाना बच जाता है, तो आप अगले मील के लिए इसे खा सकते हैं। कुछ रेसिपी बनाकर बचा हुआ खाना बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, बची हुई सब्जियों को ऑमलेट या फिर चीले में इस्तेमाल करें। सलाद में उबले हुए काबुली चना डाल दें। बचे हुए चावल से फ्राइड राइस या फिर एग राइस बना सकते हैं। इसके अलावा, आप लेफ्टओवर फूड को नए रुप में सर्व करके डिशेज बना सकते हैं। इस तरह से आप बचा हुआ खाने को खत्म कर सकते हैं।

गुड़ की चाय फटने की टेंशन खत्म! आजमाएं ये सीक्रेट टिप्स, बनेगी लाजवाब



चाय लवर हर मौसम में इसे स्वाद से पीते हैं। चाहे गर्मी हो या सर्दी चाय की लत वाले इसे खूब पीते है। चाय के दीवाने चिलचिलाती धूप में बड़े चाव से चाय पीने के शौकीन होते है। इस मौसम में या फिर सर्दियों के दौरान गुड़ की चाय पीने का एक अलग ही मजा होता है। यह स्वाद के साथ ही काफी हेल्दी होती है। लेकिन कई बार गुड़ की चाय बनाने के फट जाती है। अगर आप इसे सही तरीके से बनाएंगे तो यह कभी नहीं फटेगी। आइए आपको बताते हैं किन तरीकों से बनाएं गुड़ की टी।

सही समय पर दूध डलना जरुरी

कई लोग गुड़ की चाय बनाते समय बड़ी गलती यह करते हैं कि गुड़ के साथ ही तुरंत दूध डाल देते हैं। गुड़ को चाय के पानी में घोलते ही दूध डालें। पहले चाय के पानी में गुड़ को अच्छे से घुलने दें और इसे एक-दो उबाल आने दें। फिर गैस बंद कर दें या आंच को धीमी कर दें। चाय का तापमान कम होने बाद ही दूध को डालें।

पहले दूध को गर्म करें

अगर आप ठंडा या सामान्य तापमान का दूध उबलते हुए गुड़ वाले पानी में डल रहे, तो यह आपके चाय को फाड़ देगी। इसलिए आप दूसरे बर्नर पर दूध को गर्म करके डाल दें। इसके बाद आप गुड़ वाला घोल तैयार होने के बाद इसमें गर्म दूध को धीरे-धीरे मिश्रण में डालें। इसके अलावा, नकली गुड़ से बचें, इनमें केमिकल भरा होता है। इसलिए आप भूरा या काले रंग वाल गुड़ खरीदें। जिससे चाय अच्छी बनेंगी।

कैसे बनाएं गुड़ वाली चाय

» इसके लिए एक पैन में पानी लें और उसमें अदरक, इलायची या अन्य मसाले कूटकर डाल दीजिए।

» जब पानी उबलने लगे, तो बारीक कटा हुआ गुड़ डालें और उसे पूरी तरह से घुलने दें।

» इसके बाद आप गुड़ चाय पती डालें और चाय को अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक उबलने दें, ताकि मसाला और गुड़ का स्वाद पानी में पूरी तरह आ जाए।

» चाय का बेस जब कड़क हो जाए, तो गैस बंद कर दें या आंच बिल्कुल धीमी कर दें।

» इसके बाद आप दूसरे पैन में गर्म किया हुआ उबला हुआ दूध इस गुड़ वाले मिश्रण में धीरे-धीरे मिलाएं।

» इस मिश्रण को एक बार फिर हल्का सा आंच पर रखें और सिर्फ एक उबाल आने दें। उबाल आते ही तुरंत गैस बंद चाय को छान लें।



खाना खाते समय हम सभी उसके टेस्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर अपने खाने को तीखा या चटपटा बनाने के लिए अधिक मसालों का इस्तेमाल करते हैं। कभी-कभी तीखी चटनी या मिर्च का अचार खाने के स्वाद को बढ़ा देता है। इससे आपके टेस्ट बड को तो मजा आता है, लेकिन स्किन पर इसका उल्टा असर हो सकता है। बहुत ज्यादा तीखा खाने से चेहरे में रेडनेस व डलनेस की शिकायत होती है। वो गर्मी जो शरीर में महसूस होती है, स्किन पर भी असर डालती है, जिससे ऑयल ज्यादा बनने लगता है और चेहरा डिहाइड्रेट हो जाता है।

मसालेदार खाना खाकर चेहरा दिखने लगा है डल, तो इन आसान घरेलू नुस्खों से मिनटों में पाएं दमकती स्किन

ऐसे में अधिकतर लोग सोचते हैं कि उन्हें अपने पसंदीदा मसालेदार खाने से दूरी बनानी पड़ेगी। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने पसंदीदा खाने का लुत्फ उठाते हुए भी ग्लोइंग स्किन पा सकती हैं। बस जरूरत है कुछ आसान स्किनकेयर स्टेप्स अपनाने की। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ आसान तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जो मसालेदार खाने के बाद चेहरे की डलनेस को दूर करने में मदद करेंगे-

भरपूर पानी पीएं

अगर आप अपनी स्किन के खोए हुए ग्लो को वापिस पाना चाहती हैं तो ऐसे में आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। दरअसल, मसालेदार खाना खाने से शरीर में पसीना और गर्मी बढ़ जाती है, जिससे शरीर का पानी कम होने लगता है। इसी डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन रूखी, डल और बेजान नजर आने लगती है। इसलिए दिनभर में भरपूर पानी पीएं। इसके अलावा, नारियल पानी पीना भी काफी अच्छा रहता है। नारियल पानी से हाइड्रेशन के साथ-साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलते हैं, जिससे स्किन की नमी भीतर से बनी रहती है।

लगाएं कूलिंग फेस मास्क

मसालेदार खाने के बाद स्किन को सुकून और नमी की जरूरत होती है। इसलिए, आपको एलोवेरा, खीरा या दही से बने मास्क को स्किन पर अप्लाई करना चाहिए। यह स्किन को ठंडक देने के साथ-साथ जलन कम करता है। मास्क बनाने के लिए आप दो चम्मच दही के साथ एक चम्मच एलोवेरा जेल और कुछ बूंदे गुलाबजल मिक्स करके अप्लाई करें। करीबन 15-20 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरो धो लें। इससे स्किन को ठंडक, नमी व ग्लो मिलता है।

हाइड्रेटिंग टोनर या गुलाबजल से करें स्प्रे

मसालेदार खाने से शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है। गर्मी बढ़ने से स्किन की नमी जल्दी उड़ जाती है। ऐसे में गुलाबजल या टोनर लगाने से फायदा मिलता है। इससे चेहरा तुरंत ठंडा और फ्रेश लगता है, साथ ही पीएच बैलेंस भी बना रहता है। इसलिए, दिनभर में 2-3 बार गुलाबजल स्प्रे करें। इससे स्किन की नमी बनी रहती है। साथ ही, वह फ्रेश महसूस होती है।

फूड क्रेविंग्स से हेल्थ को हो सकता है नुकसान, इसे रीसेट करने के लिए आजमाएं ये आसान ट्रिक्स

हम सभी को अक्सर फूड क्रेविंग्स होती ही हैं। कभी-कभी कुछ मीठा खाने का मन होता है तो कभी हम कुछ चटपटा खाते हैं। जब यह क्रेविंग्स होती हैं तो हम खुद को रोक ही नहीं पाते हैं। अचानक से मन करता है कि अभी चॉकलेट चाहिए, बस अभी! ऐसे में अक्सर हम अपना फ्रिज टटोलने लग जाते हैं या फिर बाहर अपना पसंदीदा फूड खाने के लिए निकल जाते हैं। हो सकता है कि आप भी अपने टेस्ट बड अैर फूड क्रेविंग्स की वजह से परेशान हो और इससे आपकी सेहत को लगातार नुकसान हो रहा हो। हालांकि, ऐसे में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी फूड क्रेविंग्स को आसानी से रीसेट कर सकती हैं। बस आपको अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है और कुछ छोटी-छोटी आदतों को अपाने की जरूरत है। जब आप ऐसा करते हैं तो क्रेविंग्स आप पर हावी नहीं हो पाएंगी। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे ही आसान तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप फूड क्रेविंग्स को आसानी से रीसेट कर सकते हैं-

पहले पीएं पानी - अगर आपको फूड क्रेविंग्स हो रही हैं, तो ऐसे में कुछ भी खाने से पहले एक पूरा गिलास पानी पियो और फिर 10 मिनट के लिए रुक जाओ। इससे कई बार आपकी क्रेविंग्स खुद ब खुद खत्म हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि कई बार शरीर की प्यास को दिमाग भूख समझ लेता है। पानी पीने से शरीर हाइड्रेट होता है, झूठी भूख की फीलिंग कम होती है और आप बेवजह की स्नैकिंग से बच पाते हैं।

नींद के साथ समझौता नहीं - अक्सर लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं और इससे भी उनकी फूड क्रेविंग्स बढ़ने लगती हैं। दरअसल, कम नींद लेने से घ्रेलिन हार्मोन बढ़ता है और लेप्टिन हार्मोन घटता है। यही असंतुलन जंक फूड की क्रेविंग बढ़ाता है, खासकर कार्ब्स और मिठाइयों की क्रेविंग्स कई गुना बढ़ने लगती है। इसलिए रोजाना 7-8 घंटे की गहरी अवश्य लें।

करें माइंडफुल ईटिंग - अगर आप बेवजह की फूड क्रेविंग्स से बचना चाहती हैं तो ऐसे में माइंडफुल ईटिंग करना यकीनन काफी अच्छा रहता है। आप हमेशा धीरे-धीरे खाएं और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खाना खाएं। दरअसल, जब आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो ऐसे में दिमाग को समझ आता है कि पेट भर गया है। जल्दी-जल्दी खाने से ये सिग्नल कन्फ्यूज हो जाते हैं और बाद में दोबारा कुछ खाने का मन करता है, भले ही पेट भरा हो।





पाचन शक्ति बढ़ाएगा भुना जीरा या जीरा पानी? जानें कौन है सबसे बेहतर उपाय!

खराब जीवनशैली और गलत खानपान के कारण कई बीमारियां शरीर को घेर लेती है। आजकल लोग मोटापे से काफी परेशान हैं। वहीं, कुछ लोगों का डाइजेशन खराब रहता है। पेट भारी होने से उन्हें कुछ भी खाने का मन नहीं होता है। पेट की पाचन क्रिया जबरदस्त रहती है तो शरीर भी हेल्दी रहता है। खाना खाने के बाद भोजन पच नहीं रहा, तो एसिडिटी, गैस और पेट दर्द जैसी परेशानियां होने लगती है। अब आपको जानना बेहद जरुरी है कि भुना जीरा या जीरे का पानी कौन है सबसे बेहतर। आइए आपको बताते हैं-

भुना जीरा के फायदे

- ये डाइजेशन एंजाइम्स को एक्टिव करता है। यह खाना को जल्दी और आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है।

- भुना हुआ जीरा खाने से गैस और पेट फूलने की समस्या दूर हो जाती है।

- भुना हुआ जीरा सेवन करने से शरीर को ज्यादा पोषण मिलता हैं।

- इसमें पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट्स आंतों की सूजन कम करते हैं।

कैसे सेवन करें

भुना जीरा को आप अपने खाने में डाल सकती है। इसको आप सलाद, रायता, दही या सब्जी में मिलाकर सेवन कर सकती हैं।

जीरा पानी के फायदे

- जीरा पानी पीने से पेट के एंजाइम्स को एक्टिव करता है, जिससे खाना आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है।

- जीरा पानी पीने से एसिडिटी और जलन से भी राहत मिलती है।

- ये पानी शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है।

कैसे सेवन करें

आपको सुबह खाली पेट गुनगुना जीरा पानी पीना सबसे बेहतरीन माना जाता है। यह आपके पाचन को बेहतर करता है।

कौन बेहतर है- भुना जीरा या जीरा पानी

अगर आपक हल्की-फुल्की गैस है, तो भुना जीरा का सेवन कर सकते हैं। यदि आपको बार-बार एसिडिटी, कब्ज और पेट फूलने की समस्या हो रही है, तो आपको जीरा पानी का सेवन करना चाहिए। दोनों ही अपने तरीके से फायदेमंद है। आप जैसा चाहे इसका सेवन करें।

हील्स पहनकर पैरों में होता है भयंकर दर्द? इन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से पाएं तुरंत आराम!

लड़कियां स्टाइलिंग और फैशन के मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं करती। स्टाइलिश बनाने के लिए कभी-कभी लड़किया दर्द सहने को भी तैयार रहती हैं। ऑफिस, पार्टी और शादी में आउटफिट लुक को परफेक्ट बनाने के लिए महिलाएं हील्स जरुर पहनती है। हील्स पहनना सभी को पसंद है और यह लुक भी गजब का देता है। लंबे समय तक हील्स पहनने से पैरों में दर्द या फिर टखनों में जकड़न की शिकायत होने लगती है। कई बार तो दर्द इतना भंयकर होता है कि चलना-फिरना भी मुश्किल हो जाता है। आइए आपको बताते हैं कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बारे में, जो हील्स पहनने में काफी फायदेमंद रहेगी।

कफ स्ट्रेच - आमतौर पर हील्स पहनने पर पिंडलियों में टाइटनेस आ जाती है। कफ स्ट्रेच करने से उस मसल्स की टाइटनेस को कम करने में मदद करता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। आप चाहे तो वॉल के पास खड़े होकर काफ स्ट्रेच कर सकते हैं। इसे करने के लिए दीवार के सामने सीधे खड़े हो जाएं। अब एक पैर आगे और दूसरा पीछे रखें। पीछे वाला पैर एड़ी के साथ जमीन पर टिका रहे। दोनों हाथ दीवार पर रखकर थोड़ा आगे झुके, जब तक पीछे वाले पैर की पिंडली में खिंचाव न महसूस हो। इसे करीब 20-30 सेकंड ऐसे ही रुको। अब दूसरे पैर से भी इसी तरह स्ट्रेच करें।

फुट आर्च स्ट्रेच -इसे करते समय टॉवल या रेसिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल किया जाता है। हील्स पहनने से जो मसल्स टाइट हो जाती है, उन्हें ये स्ट्रेच खोलता है। इसे करने के लिए एक टॉवल या रेसिस्टेंस बैंड लो। इसे अपने पैरों के पंजे में फंसाएं और धीरे-धीरे अपनी तरफ खींचो। ऐसा करने से पैरों के आर्च और एड़ी खिंचाव फील होगा। अपने क्षमतानुसार इसी पोजिशन में रुकें और सामान्य अवस्था में लौट आएं।

एंकल रोल्स -एंकल रोल्स स्ट्रेच को आप कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं। यह आपके एंकल ज्वॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बना देता है और पैर की सूजन भी कम हो जाती है। इसे करने के लिए सबसे पहले आप कुर्सी पर बैठ जाएं। अब एक पैर ऊपर उठाओ और एंकल को पहले घड़ी की दिशा में, फिर उल्टी दिशा में घुमाओ। ऐसे ही दूसरे पैर से भी करें। इस तरह आप दोनो डायरेक्शन में 10-10 बार रोल करें।



राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

राहुल गांधी देश जलाने को तैयार हैं : गौरव भाटिया



नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर लोकतंत्र को कमजोर करने और देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे नेता बन गए हैं, जो लोकतंत्र का गला घोंटकर अराजकता लाना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति हिंसक विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा देने वाली है। भाटिया ने कहा कि भारत और भारतीय अराजकता तथा हिंसक प्रदर्शनों को पसंद नहीं करते। देश के लोगों का संविधान में विश्वास है और वे अराजकता को कुचल देते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एक लोकप्रिय वेब सीरीज के किरदार का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि उस किरदार की तरह राहुल गांधी भी सत्ता के प्रति जुनूनी हैं। भाटिया ने सीरीज के किरदार के संवाद का हवाला देते हुए कहा कि वह सत्ता पाने के लिए पूरा देश जलाने तक को तैयार है और राख का राजा बनकर भी शासन करना चाहता है।

दिल्ली प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस



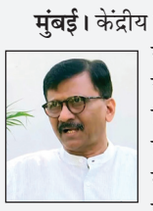
नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए। यह कार्रवाई मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर दिल्ली पुलिस की सख्ती को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी समूह विरोध प्रदर्शन के लिए किसी जगह पर अनिश्चित काल तक कब्जा करके नहीं बैठ सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, और जस्टिस जॉयमाल्य बागची तथा जस्टिस जेवी मोहना की पीठ ने किराना कमिटी दिल्ली की एक याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें त्योहारों के मौसम के दौरान विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान विरोध करने के अधिकार, पुलिस की कथित ज्यादतियों, सार्वजनिक स्थानों पर पाबंदियों और प्रदर्शनों का व्यापार पर पड़ने वाले असर को लेकर तीखी बहस हुई। व्यापारियों के संगठनों ने त्योहारों के मौसम में प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की।

राहुल के सर्वोच्च न्यायालय मार्च पर 23 नवंबर को सुनवाई



नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 12 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए मार्च के दौरान कथित हंगामे और नारेबाजी के मामले में शीर्ष अदालत 23 नवंबर को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। यह याचिका मार्च के दौरान कथित तौर पर हुए हंगामे और नारेबाजी को लेकर दायर की गई है। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। इस मार्च में राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के कई नेता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। विपक्षी नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत में याचिका दाखिल की थी।

राउत ने शाह पर महाराष्ट्र को कमजोर करने का लगाया आरोप



मुंबई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेताओं की मुलाकात पर शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह ने महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए एनसीपी के दो गुट बनाए हैं। राउत ने दावा किया कि आने वाले दिनों में दोनों गुटों का राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अजित पवार के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अनाथ हो गई है और अब यह केवल शरद पवार की पार्टी है। राउत ने शिवसेना को लेकर भी कहा कि असली शिवसेना केवल उद्धव ठाकरे की है। उनके मुताबिक, दोनों दलों के नेता भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक अन्य बयान में दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। उनका यह बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस में बढ़ी दरार रुहुल्ला ने पार्टी को कहा अलविदा

बडगाम। सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने समर्थकों की भारी मौजूदगी के बीच मंच से जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने का एलान कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह अब पार्टी का हिस्सा नहीं हैं और खुद को नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग कर रहे हैं। रुहुल्ला ने सभा में पहुंचे लोगों का आभार जताते हुए कहा, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप यहां आए। यहां कुर्सी संभालनी नहीं, बल्कि कुर्सी से उतरना था। उन्होंने कहा कि मंगलवार दोपहर 2:40 बजे तक वह नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे, लेकिन अब वह खुद को पार्टी से आजाद करते हैं। रुहुल्ला ने अपना इस्तीफा मोहम्मद अशरफ मट्टू को सौंपा और उनसे कहा कि वह इसे अपने हाथों से संबंधित लोगों तक पहुंचाएं। अशरफ मट्टू के बेटे तुफैल मट्टू की वर्ष 2010 में श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में पुलिस फायरिंग के दौरान मौत हो गई थी। समर्थकों का कहना है कि रुहुल्ला ने यह फैसला काफी सोच-विचार के बाद लिया है। उनके लिए पद और सत्ता से ज्यादा जनता का भरोसा और उनके मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। लोगों ने उम्मीद जताई कि सच और जनता के अधिकारों की लड़ाई में वे रुहुल्ला के साथ खड़े रहेंगे।

पुणे को मिली मेट्रो की नई सौगात, पुरानी सरकार रहती तो कई दशक और करना पड़ता इंतजार : मोदी

पुणे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुणे मेट्रो की बहुप्रतीक्षित लाइन-3 का उद्घाटन किया। मान-हिंजवडी से शिवाजीनगर तक जाने वाली इस मेट्रो लाइन से पुणे के आईटी हब, प्रमुख व्यावसायिक और प्रशासनिक इलाकों के बीच आवाजाही आसान होने की उम्मीद है। हालांकि, यात्रियों के लिए मेट्रो सेवाएं चार नवंबर को सुबह छह बजे से शुरू होंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही।

पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में जब देश ने एनडीए को सेवा का मौका दिया, तो हम एक संकल्प लेकर चले। यह संकल्प था, शहर में रहने वाले मिडिल क्लास की ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और इसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज, किसी शहर को दो मुख्य पैमानों पर परखा जाता है, पहला वह शहर कितना प्रतिस्पर्धी है? दूसरा, उसका ईज ऑफ़ लिविंग इंडेक्स (जीवन सुगमता सूचकांक) कितना ऊंचा है? मेट्रो परियोजनाएं इन दोनों पैमानों में योगदान देती हैं, जिससे शहर अधिक कार्यकुशल, सुलभ और रहने के लिए बेहतर बनता है।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज का दिन प्रो पीपल, प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस का भी उदाहरण है। हमारे देश में पहली मेट्रो 1984 में चली थी। उसके बाद के 30 साल में सिर्फ 248 किमी मेट्रो लाइन बनी। 2014 तक देश में सिर्फ पांच शहरों में मेट्रो चल रही थी। अगर वही पुरानी सोच चलती, पुरानी सरकार रहती, पुरानी कार्य संस्कृति रहती, तो पुणे में मेट्रो पहुंचने में कई और दशक लग जाते।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे शहर केवल रहने की जगह नहीं हैं। ये देश की आर्थिक गतिविधि के बड़े केंद्र भी हैं। हमें देश के सैकड़ों छोटे शहरों को ग्रोथ हब भी बनाना है। इसी विजन के साथ इस साल फरवरी में अर्बन चैलेंज फंड की स्वीकृति दी गई थी। इस फंड के लिए एक लाख करोड़ रुपये की मदद केंद्र सरकार दे रही है। इससे आने वाले वर्षों में देश के शहरों में लाखों करोड़ रुपये का



निवेश जुटने का लक्ष्य है। मैं स्थानीय निकायों और प्राइवेट सेक्टर के साथियों से आगे आने का आग्रह करता हूं। हम सभी को मिशन मोड पर जुटना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुणे शहर हमेशा से ऐसे विचारों का केंद्र रहा है, जिनसे राष्ट्र और समाज को नई दिशा मिली है। आज पुणे विकसित भारत की नई ऊर्जा को भी दिशा दे रहा है। आईटी, ऑटोमोबाइल, फार्मा, स्टार्टअप... इनोवेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, पुणे देश के युवाओं के लिए सपनों और संकल्प का स्थान है। ऐसे में यहां की मजबूत होती मेट्रो कनेक्टिविटी यहां के विकास को नई गति देने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि त्योहारों की खुशियां तब और बढ़ जाती हैं, जब जीवन में कोई नई सुविधा जुड़ती है। आज पुणे के लोगों के लिए ऐसा ही सुखद अवसर है। मुझे खुशी है कि आज पुणे मेट्रो की एक और लाइन का लोकार्पण हो रहा है। 10 वर्ष पहले मुझे पुणे में पहले चरण के काम के शिलान्यास का अवसर मिला था। अब हिंजेवाड़ी से शिवाजी नगर के बीच मेट्रो शुरू होने से पुणे के आईटी हब को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। आज जिस नई लाइन पर काम शुरू हुआ है, उससे पुणे के पुराने और नए इलाकों के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। मैं पुणे और महाराष्ट्र के सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश की अनेक पीढ़ियां गरीबी हटाओ के वादों और अवशेषों के बीच ही बड़ी हुई हैं। पहले गरीबी से लड़ाई सिर्फ नारों में थी, आज भारत गरीबी को हरा रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत वो देश है, जो सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी है और सबसे तेजी से गरीबी कम करने वाला भी है।

पिछले 12 वर्षों में देश में मेट्रो परिवहन में बड़ा बदलाव आया है। मेट्रो नेटवर्क, जो 2014 में 248 किमी था, अब 1,400 किमी तक विस्तारित हो गया है। 2014 में, मेट्रो सेवाएं केवल पांच शहरों में चालू थीं। आज उनका विस्तार 26 शहरों तक हो गया है। अब हर दिन एक करोड़ से ज्यादा लोग मेट्रो से यात्रा करते हैं। भारत का मेट्रो नेटवर्क अब दुनिया के शीर्ष तीन मेट्रो नेटवर्क में गिना जाता है।

पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएमआरडीए) के आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने बताया कि लाइन-3 पूरी तरह से एलिवेटेड यानी जमीन से ऊपर बना 23.203 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर है। इसे पुणेरी मेट्रो और पिंक लाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह मान से शुरू होकर हिंजवडी के राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क से होते हुए शिवाजीनगर तक पहुंचेगी।

इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 8,313 करोड़ रुपये है। इसमें भूमि अधिग्रहण और उपयोगिता सेवाओं को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का खर्च भी शामिल है। इसे केंद्र सरकार की नेशनल मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के तहत डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) मॉडल पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत तैयार किया गया है।

इस मेट्रो कॉरिडोर पर कुल 23 स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें से 17 स्टेशन यात्रियों के लिए खोले जाएंगे। हालांकि, सात स्टेशनों पर शुरुआत में केवल एक सीढ़ी चालू रहेगी। यात्रियों को मेटो स्टेशन से उतरने के बाद बस, पैदल या दूसरे परिवहन साधनों से आगे की यात्रा करने में परेशानी न हो, इसके लिए मल्टी-मोडल इंटीग्रेशन की व्यवस्था की जा रही है। मेट्रो परियोजना के साथ सड़क यातायात को बेहतर बनाने और पैदल चलने वालों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। इसके तहत अलग साइकिल ट्रैक, चौड़े फुटपाथ, पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग और फुट ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। डॉ. अभिजीत चौधरी के मुताबिक, इस मेट्रो लाइन से खासकर हिंजवडी इलाके में ट्रैफिक जाम कम करने में काफी मदद मिलेगी।

घुसपैठियों को भारत में रखना चाहते हैं राहुल और ममता : शुभेंदु अधिकारी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली पर निशाना साधा। यह रैली दो दिन पहले कथित चुनावी गड़बड़ियों को लेकर आयोजित की गई थी। अधिकारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को बचाने के लिए हाथ मिला लिया है।

सिलीगुड़ी के बागडोगरा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए, अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार और



चुनाव आयोग (ईसी) देश से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी की भी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में उन्हें किसी ने एक भी दुर्गा पूजा का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित नहीं किया था।

अधिकारी ने कहा, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम अपने हाथ में लिया है, जबकि ममता बनर्जी और राहुल गांधी उन्हें भारत में बनाए रखने के लिए मिलकर लड़ रहे हैं। मंगलवार को, बंगाल के मुख्यमंत्री का उत्तरी बंगाल में पार्टी के एक कार्यक्रम और राज्य सरकार के एक आयोजन में शामिल होने का कार्यक्रम है।

मॉक संसद में राहुल पीएम बनें, संसद में मोदी ही होंगे : हिमंत

■ दिल्ली-गुवाहाटी बुलेट ट्रेन को मिली मंजूरी

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थीं और इसके लिए कई प्रयास भी किए गए। जब उनका कोई प्रयास सफल नहीं हुआ तो कांग्रेस नेताओं ने मल्लिकार्जुन खरगे के आवास के लॉन में मॉक संसद का आयोजन किया गया और



वहां राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। सरमा ने कहा कि हकीकत यह है कि मॉक संसद में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और संसद में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे।

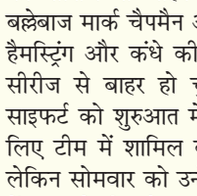
दिल्ली से गुवाहाटी तक बुलेट ट्रेन लाइन को मंजूरी मिलने पर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को मंजूरी मिल गई है, हालांकि इसे आगे बढ़ाने के लिए अभी कई प्रक्रियाएं पूरी करनी बाकी हैं। सरमा ने कहा कि सबसे अच्छी खबर यह है कि गुवाहाटी अब बुलेट ट्रेन के नक्शे पर आ गया है। इस परियोजना के लिए चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर मार्ग तय किए जाने को उन्होंने काफी अहम बताया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वो दिल्ली जाकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करेंगे। इसके बाद परियोजना से जुड़ी और जानकारी सामने आएगी। उन्होंने इसे बेहद उल्लेखनीय, साहसिक और दूरदर्शी फैसला बताया। सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की वजह से ही असम को इस परियोजना की मंजूरी मिली है। उनके मुताबिक, यह फैसला राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत के खिलाफ पहले वनडे से बाहर हुए डेवोन कॉनवे

ऑकलैंड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार से शुरू होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज से पहले मेजबान टीम को बड़ा झटका लगा है। न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज डेवोन कॉनवे चोट के कारण पहले वनडे से बाहर हो गए हैं। मंगलवार को ईडन पार्क में अभ्यास सत्र के दौरान तेज गेंदबाज मैट हेनरी से टकराने के बाद उन्हें सिर में चोट लगी। जांच में उन्हें कन्कशन (सिर में चोट के कारण मस्तिष्क की कार्यप्रणाली प्रभावित होना) की पुष्टि हुई है।



न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। अभ्यास के दौरान कॉनवे और हेनरी कैच लेने की कोशिश कर रहे थे, तभी दोनों खिलाड़ियों के बीच टक्कर हो गई। घटना के तुरंत बाद मेडिकल स्टाफ ने दोनों का उपचार किया और सिर की चोट से जुड़ी जांच की।

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बयान में कहा, कॉनवे को आगे की जांच के लिए अस्पताल के आपातकालीन विभाग ले जाया गया। जांच में कन्कशन की पुष्टि हुई है, जिसके कारण वह कल भारत के खिलाफ होने वाले पहले वनडे में नहीं खेल पाएंगे। बोर्ड ने यह भी बताया कि दोनों खिलाड़ियों की निगरानी जारी रहेगी और भारत के खिलाफ हीरो वीडा वनडे सीरीज में उनकी आगे की उपलब्धता पर नजर रखी जाएगी। कॉनवे न्यूजीलैंड के उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं, जो चोट के कारण इस पांच मैचों की सीरीज से बाहर हो चुके हैं। इससे पहले बल्लेबाज मार्क चैपमैन और रचिन रवींद्र भी क्रमशः हैमस्ट्रिंग और कंधे की चोट के कारण पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं। न्यूजीलैंड ने टिम साइफर्ट को शुरुआत में केवल पहले दो वनडे के लिए टीम में शामिल करने पर विचार किया था, लेकिन सोमवार को उन्हें पूरी सीरीज के लिए टीम में जगह दे दी गई।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

शेयर बाजार में लगातार तेजी सेंसेक्स 1225 अंक चढ़कर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजारों में मंगलवार को जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। बेंचमार्क इंडेक्स लगातार चौथे सेशन में बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1225 अंकों की उछाल के साथ 76917 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 370 अंक चढ़कर 23810 पर बंद हुआ है। सबसे ज्यादा खरीदारी एफएमसीजी, रियल्टी समेत फाइनेंशियल्स सर्विसेज में हुई। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 3.6 फीसदी उछला। बड़ी कंपनियों के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी तेजी रही। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 1 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 0.2 फीसदी चढ़ा। निफ्टी कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स में 4.5 फीसदी की जोरदार बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी में बीएसई 5% की तेजी के साथ टॉप गेनर रहा। नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्युमर, एशियन पेंट्स में 4-4 फीसदी से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई।

टीवी-फ्रिज से लेकर मिठाई और ड्राई फ्रूट्स तक हुए महंगे

नई दिल्ली। दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में खरीदारी तेज हो गई है लेकिन इस बार महंगाई ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। टीवी, फ्रिज और एसी खरीदने से लेकर मिठाई और ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी तक, हर चीज के लिए ग्राहकों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों, खराब फसल और माल ढुलाई महंगी होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद 3 से 7 फीसदी तक महंगे हो गए हैं। वहीं मिठाइयों के दाम में भी 15 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा उछाल पिस्ता की कीमतों में देखने को मिला है, जिसके भाव पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुने हो गए हैं। दिवाली पर टीवी, फ्रिज और एसी की मांग बढ़ जाती है। इसी बीच हायर, एलजी और ब्लू स्टार जैसी कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतों में इजाफा किया है।

टाटा की ईवी गाड़ियों की सेल 75 प्रतिशत तक उछली

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन ने अक्टूबर में भारतीय कार बाजार को जमकर रफ्तार दी। दिवाली की खरीदारी का असर कंपनियों की बिक्री के आंकड़ों में साफ दिखा। कई कंपनियों ने अपने अब तक के सबसे ऊंचे मासिक आंकड़े छुए, और इलेक्ट्रिक कारों की मांग भी तेजी से बढ़ी। हुंडई मोटर इंडिया ने अक्तूबर में 62,799 कारें घरेलू बाजार में बेचीं, जो उसकी अब तक की सबसे ज्यादा मासिक घरेलू बिक्री है। इसमें वेन्यू के 13,017 यूनिट भी शामिल हैं, जो इस मॉडल का अपना सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा है। टाटा की ईवी बिक्री 75% बढ़कर 16,244 यूनिट हो गई, जबकि पिछले साल अक्टूबर में यह 9,286 यूनिट थी। महिंद्रा की घरेलू एसयूवी बिक्री 73,338 वाहनों के रिकॉर्ड पर पहुंची, और एक्सपोर्ट को मिलाकर कंपनी की कुल बिक्री 1,31,109 वाहन रही, यानी 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी।

भारत में बदल रहा है कोल्ड ड्रिंक का बाजार

नई दिल्ली। भारत के करीब 60 हजार करोड़ रुपए के सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब लोग मीठी कोल्ड ड्रिंक्स की जगह जीरो शुगर और लो शुगर वाले पेय पदार्थों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसका फायदा पेप्सी और कोका-कोला जैसी बड़ी कंपनियों को मिल रहा है। जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही में पेप्सीको के कुल वॉल्यूम में जीरो और लो शुगर ड्रिंक्स की हिस्सेदारी बढ़कर 88% हो गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 44% थी। वहीं, कोका-कोला की डाइट और लाइट ड्रिंक्स की बिक्री भी तेजी से बढ़ी है। लोगों की बदलती पसंद के बीच चीनी की बढ़ती कीमतें भी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। पिछले साल 40 से 50 रुपए किलो मिलने वाली चीनी अब 58 से 65 रुपए किलो तक पहुंच गई है।

भारत के बाजार में गिरावट के कारण और समाधान

ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, अक्तूबर में सुधार के बावजूद भारतीय शेयर आज उभरते बाजारों की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली परिसंपत्तियों में शुमार हैं। बैंचमार्क निफ्टी 50 इंडैक्स इस साल 12 प्रतिशत गिरा है (डॉलर के संदर्भ में 17 प्रतिशत)। प्रमुख उभरते बाजारों में केवल इंडोनेशियाई शेयरों का प्रदर्शन इससे भी बदतर रहा है, जहां मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनैशनल (एम.एस.सी.आई.) द्वारा यह चेतावनी दिए जाने के बाद कि इंडोनेशिया अपना उभरते बाजार का दर्जा खो सकता है, बैंचमार्क आई.डी.एक्स. कंपोजिट इंडैक्स इस साल 42 प्रतिशत गिरा है (डॉलर के संदर्भ में 46 प्रतिशत)। भारतीय बाजारों में यह गिरावट आंशिक रूप से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफ.पी.आई.) द्वारा बड़े पैमाने पर की गई बिकवाली के कारण है, जिन्होंने इस साल अब तक भारतीय इक्विटी बाजारों से लगभग 3 ट्रिलियन रुपए निकाले हैं, जो कि एक दशक का उच्चतम स्तर है। इस पूंजी निकासी ने रुपए को कमजोर किया है और परिणामस्वरूप भारतीय इक्विटी से विदेशी निवेशकों को मिलने वाले डॉलर रिटर्न को कम कर दिया है।

इस मंदी के लिए कई प्रतिस्पर्धी व्याख्याएं मौजूद हैं। एक सिद्धांत देश में आर्टिफिशियल इंटैलिजैंस (ए.आई.) कंपनियों की कमी की ओर इशारा करता है। चूंकि निवेशकों ने ए.आई. फर्मों और ए.आई. से जुड़े क्षेत्रों में भारी मात्रा में डॉलर लगाए हैं, इसलिए भारत पीछे छूट गया है। इस सिद्धांत के अनुसार, जैसे ही ए.आई. से जुड़ा व्यापार धीमा पड़ेगा, भारत को लाभ हो सकता है। दूसरा सिद्धांत भू-राजनीतिक तनावों पर जोर देता है, जिन्होंने कमोडिटी की कीमतों को बढ़ा दिया है। एक बड़े कमोडिटी आयातक के रूप में, भारत पर बाकियों की तुलना में अधिक असर पड़ा है। इससे संबंधित, अमरीका में बढ़ती मुद्रास्फीति और बॉन्ड



यील्ड ने अमरीकी और उभरते बाजार की परिसंपत्तियों के बीच के अंतर को कम कर दिया है, जिससे उभरते बाजारों में आने वाले फंड का प्रवाह कमजोर हुआ है। इस सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि जैसे ही भू-राजनीतिक तनाव शांत होंगे और वैश्विक कमोडिटी चक्र ठंडा पड़ेगा, भारत फिर से निवेशकों की पसंद बन जाएगा।

तीसरा सिद्धांत बड़ी भारतीय कंपनियों में नवाचार (इनोवेशन) की कमी पर जोर देता है। लगातार कमाई में वृद्धि के वादे के बिना, भारतीय शेयर विदेशी निवेशकों के लिए अनाकर्षक बने रहेंगे, जैसा कि बर्नस्टीन रिसर्च के विश्लेषकों वेणुगोपाल गारे और निखिल अरेला ने कुछ सप्ताह पहले ग्राहकों को लिखे एक नोट में कहा था। उन्होंने लिखा कि यदि ए.आई. का व्यापार कमजोर होता है या तेल की कीमतें गिरती हैं, तो विदेशी पूंजी अस्थायी रूप से लौट सकती है। लेकिन निरंतर प्रवाह इस बात पर निर्भर करेगा कि 'क्या भारत प्रतिस्पर्धात्मकता, नवाचार और वैश्विक प्रासंगिकता के नए इंजन बना सकता है?' इस जोड़ी ने तर्क दिया कि अंतरिक्ष, रक्षा, सैमीकंडक्टर और डीप-टैक जैसे क्षेत्रों में उभरने वाली नई फर्में वर्तमान में बड़े पैमाने पर वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने के लिए बहुत छोटी हैं।

इनमें से कोई भी व्याख्या यह संकेत नहीं देती कि कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव विदेशी फंडों को वापस ला सकते हैं। निश्चित रूप से, हमारे कैपिटल टैक्स ढांचे में विकृतियां हैं और इनका समाधान किया जाना चाहिए। कैपिटल गेन्स टैक्स को तर्कसंगत बनाने से विदेशी और घरेलू निवेशकों को अपने लिए अधिक उपयुक्त परिसंपत्तियां चुनने में मदद मिलेगी। लेकिन वे पूंजी के बहिर्वाह (आऊटफ्लो) को रोकने के लिए कोई त्वरित समाधान नहीं है। वर्तमान मंदी में शेयरों का पुनर्निर्धारण (रीप्राइसिंग) अपने आप में भारतीय बाजारों में फिर से रुचि जगा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि विदेशी निवेशकों ने हाल के दिनों में आरंभिक सार्वजनिक निर्गमों (आई.पी.ओज) में भारी निवेश किया है, भले ही उन्होंने सैकेंडरी मार्केट में अत्यधिक महंगे शेयरों से परहेज किया हो। नीति निर्माताओं को ऐसे कठिन सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो देश में उच्च-मूल्य वाली, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फर्मों के विकास को गति दे सकें। इन फर्मों को अपने संसाधनों को नौकरशाही से निपटने में खर्च करने की बजाय इनोवेटिव उत्पाद विकसित करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।

एनआईटी रायपुर के 17वें दीक्षांत समारोह में 1,364 विद्यार्थियों को मिली उपाधियां

विकसित भारत के निर्माण में युवा इंजीनियरों और वैज्ञानिकों भूमिका महत्वपूर्ण : रेड्डी

रायपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर का 17वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में गरिमामय वातावरण में आयोजित हुआ। समारोह में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर संस्थान के 1,364 विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों की उपाधियां प्रदान की गईं। विभिन्न संकायों में उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को कुल 51 पदकों से सम्मानित किया गया।



दीक्षांत समारोह के साथ ही एनआईटी रायपुर में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने संस्थान में सात अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। ये केंद्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष अनुसंधान, एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी, ग्रामीण एवं जनजातीय स्वास्थ्य तथा सतत ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उच्चस्तरीय अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देंगे।

समारोह में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की महानिदेशक और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) की सचिव डॉ. एन. कलैसेल्वी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। समारोह की अध्यक्षता एनआईटी रायपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉ. सुरेश हावरे ने की। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रो. एन. वी. रमण राव, सीनेट एवं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य, प्राध्यापक, प्रशासनिक अधिकारी, विद्यार्थी और उनके अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने विद्यार्थियों से विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को यह संकल्प लेना चाहिए कि विकसित भारत के निर्माण में उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।

उन्होंने कहा कि आज देश ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन और कृषि विकास सहित अनेक क्षेत्रों में नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। युवा इन चुनौतियों को बाधा के रूप में देखने के बजाय अवसर के रूप में स्वीकार करें। देश को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला सहित विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए समाधान और तकनीक विकसित करना समय की आवश्यकता है।

श्री रेड्डी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान और रटने की प्रवृत्ति तक सीमित रखने के बजाय कौशल आधारित, व्यावहारिक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत विनिर्माण तकनीक भविष्य की अर्थव्यवस्था तथा रोजगार के प्रमुख आधार बनेंगे।

आत्मविश्वास और परिश्रम से बनाएं अपनी पहचान : राज्यपाल डेका



पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विवि के सप्तम दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि युवा आत्मविश्वास, निरंतर प्रयास और अपनी विशिष्ट प्रतिभा के बल पर जीवन में आगे बढ़ें। असफलता से घबराने के बजाय उसके कारणों को समझें और गलतियों से सीखकर पुन: प्रयास करें। शिक्षा का उपयोग व्यक्तिगत सफलता के साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भी होना चाहिए। राज्यपाल आज पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के सप्तम दीक्षांत समारोह को अध्यक्षीय आसंदी से संबोधित कर रहे थे। समारोह में पिछले पांच वर्षों के 24 हजार 800 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा की उपाधियां प्रदान की गईं।

समारोह में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, विधायक श्री धरमलाल कौशिक एवं श्री सुशांत शुक्ला, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र शर्मा, नेक अध्यक्ष श्री नागेश्वर राव, विश्वविद्यालय के कुलपति श्री वीरेंद्र कुमार सारस्वत तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की उन्नत आधिकारिक वेबसाइट का लोकार्पण और स्मारिका 'अभ्युदय' का विमोचन किया गया। विश्वविद्यालय की ओर से एकलव्य विद्यालय देवपहरी के 311 विद्यार्थियों को बैग, स्वेटर, टिफिन एवं पानी की बोतलें वितरित की गईं।

राज्यपाल श्री डेका ने उपाधि एवं पदक प्राप्त विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियों में अभिभावकों, गुरुजनों और शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान है। दीक्षांत समारोह जीवन में नई ऊर्जा और नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मुक्त विश्वविद्यालय दूरस्थ क्षेत्रों तक ज्ञान पहुंचाने और शिक्षा के अवसरों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

महादेव सट्टा एप के खिलाफ 72 एफआरआई भूपेश सरकार ने किया था : दीपक बैज

रायपुर। महादेव सट्टा एप में सौरभ चंद्राकर को प्रत्यार्पण बहुत देरी से की गयी। बहुत छोटी कार्यवाही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि महादेव सट्टा एप के सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाया जाना संभव हो सका तो उसके पीछे कांग्रेस की भूपेश सरकार के ठोस प्रयास है। महादेव सट्टा एप के खिलाफ पहली एफआईआर से लेकर 72 एफआईआर तक दर्ज करने की ठोस कार्यवाहियां कांग्रेस की सरकार ने किया था। 500 से अधिक जप्तियां और गिरफ्तारियां भी कांग्रेस की सरकार ने ही किया था। सौरभ चंद्राकर को तो



लाया गया है लेकिन रवि उप्पल, शुभम सोनी को कब लाया जायेगा? महादेव सट्टा एप को गूगल प्ले पर से कांग्रेस की भूपेश सरकार के अनुरोध पर ही हटाया गया था। कांग्रेस की सरकार के समय ही रायपुर पुलिस की अर्जी पर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ था। गेमिंग एप के खिलाफ सख्त कानून भी कांग्रेस की भूपेश सरकार ने ही बनाया था। इसके पहले तो गेमिंग सट्टा एप के खिलाफ भारत में कोई कानून ही नहीं था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि महादेव सट्टा एप को लेकर भाजपा ने विधानसभा चुनाव के पहले खूब प्रोपेगंडा किया लेकिन डबल इंजन की सरकार के बाद भी पिछले 3 साल से महादेव सट्टा एप क्यों बंद नहीं हुआ? आज भी महादेव सट्टा एप के विज्ञापन सोशल मीडिया साइट्स पर उपलब्ध है।

चक्रवाती तूफान मुरासु के प्रभाव से बस्तर का मौसम बदला हल्की बूदा-बांदी जारी

जगदलपुर। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान मुरासु के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से यानी बस्तर संभाग के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है सोमवार सुबह से ही बादल छाये हुए हैं, इसके साथ ही दिन भर रुक-रूककर हल्की बूदा-बांदी होती रही, बीती रात में भी बस्तर में बारिश हुई है । मौसम विभाग के अनुसार 3 नवंबर को बस्तर में तेज रफ्तार हवाओं के साथ मध्यम बारिश की पूरी संभावना है। एचपी मौसम वैज्ञानिक (एसपी) चंद्रा ने बताया कि चक्रवात मुरासु पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ इस तूफान के सीधे केंद्र में नहीं है।

सरगुजा ओलंपिक में ग्रामीण प्रतिभाओं का दिखेगा दम, 88 हजार खिलाड़ियों ने कराया पंजीयन

सरगुजा। छत्तीसगढ़ के गांवों और शहरों में छिपी खेल प्रतिभाओं को अब बड़ा मंच मिल रहा है। सरगुजा जिले में खेलों को जनभागीदारी से जोड़ने और स्थानीय खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक 2026-27 का मंगलवार को अम्बिकापुर के गांधी स्टेडियम में भव्य शुभारंभ हुआ। तीन दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में जिले के सात विकासखंडों के करीब 1800 खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा और दमखम दिखाएंगे। खास बात यह है कि सरगुजा के खेल इतिहास में पहली बार फ्लड लाइट की रोशनी में फुटबॉल मैच खेला



जाएगा।

लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने फुटबॉल को किक मारकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि खेल में आगे बढ़ने के लिए निरंतर अभ्यास, अनुशासन और मेहनत जरूरी है। खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने के साथ खेल भावना और नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरगुजा के खिलाड़ी संभाग, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।

सरगुजा ओलंपिक के प्रति जिले में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। प्रतियोगिता के लिए 1 अगस्त से 15 सितंबर तक हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीयन में कुल 88,509 खिलाड़ियों ने नाम दर्ज कराया। इनमें 36,319 पुरुष और 52,190 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। सबसे ज्यादा 48,626 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स के लिए पंजीयन कराया। यह आंकड़ा जिले में खेलों के प्रति बढ़ती रुचि और ग्रामीण प्रतिभाओं की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

नगरीय निकाय चुनाव में बनेगी भाजपा की सरकार :संतोष

रायपुर। आगामी नगरीय निकाय चुनावों को ले**कर भारतीय** जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि पंचायत स्तर और पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक अंत्योदय का भाव जन-जन तक पहुँचे, यह भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और रीति-नीति रही है। वार्ड पार्षद



विकास की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। जिस प्रकार पंचायतें ग्रामीण विकास का जरिया बनती हैं, ठीक उसी तरह नगर निगम और नगर पालिकाएँ शहरों के सर्वांगीण विकास का माध्यम हैं। श्री पाण्डेय ने कहा कि डबल इंजन सरकार के साथ-साथ शहरों में नगर सरकार की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। पाण्डेय ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आहूत बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी नगर निकाय चुनावों में भी जनता के आशीर्वाद से शहरों में भाजपा की नगर सरकार बनेगी। मैदान में उतरने से पहले की पूर्व तैयारी के तहत पार्टी अपने बूथों और शक्ति केन्द्रों को सुदृढ़ कर रही है। इसके तहत बूथ समितियों की समीक्षा की जा रही है कि वे पूरी तरह दुरुस्त हैं या नहीं? यदि कहीं नई नियुक्तियाँ कर संगठन को सक्रिय करने की आवश्यकता है, तो उसे समय रहते पूरा किया जा रहा है।

चक्रवाती तूफान मुरासु के प्रभाव से बस्तर का मौसम बदला

जगदलपुर। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान मुरासु के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से यानी बस्तर संभाग के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है सोमवार सुबह से ही बादल छाये हुए हैं, इसके साथ ही दिन भर रुक-रूककर हल्की बूदा-बांदी होती रही, बीती रात में भी बस्तर में बारिश हुई है । मौसम विभाग के अनुसार 3 नवंबर को बस्तर में तेज रफ्तार हवाओं के साथ मध्यम बारिश की पूरी संभावना है।

एचपी मौसम वैज्ञानिक (एसपी) चंद्रा ने बताया कि चक्रवात मुरासु पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ इस तूफान के सीधे केंद्र में नहीं है, लेकिन इसके आउटर क्लाउड बैंड का आंशिक प्रभाव बस्तर संभाग में 03 नवंबर को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इस दौरान संभाग के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और बस्तर के कई इलाकों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी व तेज हवाएं चल सकती हैं। रुक-रुक कर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बौछारें पडऩे का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बारिश और बादलों की आवाजाही के चलते दिन के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। चक्रवाती तूफान मुरासु को लेकर बस्तर संभाग के किसानों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। वर्तमान में क्षेत्र में धान कटाई और मिंजाई का दौर चल रहा है।

बिना रेरा पंजीयन भूखंडों की बिक्री पर बालाजी बिल्डर्स पर 20 लाख का अर्थदंड

रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजी रेरा) ने बिना अनिवार्य रेरा पंजीयन के भूखंडों का विक्रय करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भिलाई की मेसर्स बालाजी बिल्डर्स पर 20 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। प्राधिकरण ने भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत यह कार्रवाई की है। इसके साथ ही संबंधित प्रमोटर को परियोजनाओं का नियमानुसार रेरा पंजीयन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुसार, मेसर्स बालाजी बिल्डर्स के प्रोपराइटर श्री जुगल किशोर तिवारी, निवासी शिव अर्पण बिल्डिंग, दक्षिण गंगोत्री, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग द्वारा प्रियंका नगर स्थित खसरा क्रमांक 617/17 तथा आदर्श नगर स्थित खसरा क्रमांक 95/43 की भू-संपदा परियोजनाओं के अंतर्गत भूखंडों का विक्रय किया गया था। इन परियोजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ रेरा में अनिवार्य पंजीयन नहीं कराया गया था। प्रकरण की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि संबंधित प्रमोटर द्वारा परियोजना की भूमि का विभाजन कर भूखंडों का विक्रय किया गया तथा खरीदारों से विक्रय प्रतिफल के रूप में राशि भी प्राप्त की गई।

सरकार, पटवारियों की हड़ताल समाप्त नहीं होने देना चाह रही : कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार आंदोलनरत पटवारियों की जायज मांगों पर बातचीत कर समाधान निकालने के बजाय उन्हें सस्पेंड कर रही। 50 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया, नौकरी में ज्वाइन नहीं करने पर सर्विस



इन ब्रेक की धमकी दी जा रही है। सरकार का यह रवैया बेहद अलोकतांत्रिक, तानाशाहीपूर्ण और निंदनीय है। कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें सस्पेंड करना भाजपा सरकार की दमनकारी कार्यशैली को उजागर करता है।

प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पटवारियों की हड़ताल के कारण धान खरीदी की तैयारी बाधित हो रही। किसान परेशान है उनका पंजीयन नहीं हो रहा। खसरा खतौनी दुरूस्त नहीं हो रहा है। सरकार जानबूझकर पटवारियों की हड़ताल को समाप्त नहीं करवा रही ताकि धान कम खरीदना पड़े। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पटवारी राजस्व विभाग द्वारा थोपे गए नए पीवी ऐप यानी फिजिकल वेरिफिकेशन ऐप का विरोध कर रहे हैं। इस ऐप के जरिए डिजिटल सर्वे और जीपीएस फोटो अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।

पीएम केयर्स योजना से मोनिका बघेल के खाते में पहुंचे 10 लाख रुपये

रायपुर। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत बालोद जिले की बालिका सुश्री मोनिका बघेल को 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की गई है। भारत सरकार की ओर से यह राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने मोनिका को डेमो चेक प्रदान किया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य



कार्यपालन अधिकारी, अपर कलेक्टर, जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला बाल संरक्षण अधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही गैर-संस्थागत देखरेख एवं संस्थागत देखरेख के संरक्षण अधिकारी, मिशन शक्ति के परियोजना समन्वयक, मिशन वात्सल्य के अधिकारी-कर्मचारी तथा मोनिका के संरक्षक भी मौजूद रहे। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत 29 मई 2021 को कोविड-19 महामारी से प्रभावित उन बच्चों को सहायता देने के उद्देश्य से की गई थी, जिन्होंने महामारी के दौरान अपने माता-पिता, कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता को खो दिया था। योजना के तहत प्रत्येक पात्र बच्चे के नाम पर 10 लाख रुपये का कॉर्पस फंड तैयार किया जाता है। 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बच्चे को 23 वर्ष की आयु तक मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है।

मुख्यमंत्री श्री साय से सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ और थर्ड पार्टी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने की मुलाकात

मुख्यमंत्री साय की पहल पर बीएसपी के हजारों आवासधारियों को बड़ी राहत

रायपुर। भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) की टाउनशिप में रहने वाले हजारों परिवारों की लंबे समय से चली आ रही आवास किराए की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के बाद बीएसपी प्रबंधन ने रिटेंशन स्कीम तथा थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासों का किराया घटाकर 6 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह कर दिया है। इस फैसले से करीब चार हजार आवासधारियों को राहत मिलने का अनुमान है। विशेष रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह निर्णय आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि रिटेंशन श्रेणी में किराए की दर 75 प्रतिशत कम हुई है।

इस बीच मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में



भिलाई स्टील प्लांट के सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ और थर्ड पार्टी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, विधायक श्री ललित चंद्राकर एवं श्री रिकेश सेन सहित दुर्ग-भिलाई के अनेक जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

बीएसपी टाउनशिप के आवासधारियों को बढ़े हुए किराए के कारण हो रही परेशानियों का विषय मुख्यमंत्री श्री साय की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में प्रमुखता से रखा गया था। बैठक के दौरान रिटेंशन और थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासों के लिए निर्धारित अलग-अलग किराया दरों तथा उनमें हुई वृद्धि से उत्पन्न परिस्थितियों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अन्य प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए समस्या का व्यावहारिक एवं संवेदनशील समाधान निकालने पर जोर दिया था। मुख्यमंत्री की पहल पर जनप्रतिनिधियों और बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई चर्चा में किराया दरों के संशोधन पर सहमति बनी।

इसके बाद बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग ने 2 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर नई किराया दर निर्धारित की। संशोधित आदेश के अनुसार रिटेंशन और थर्ड पार्टी, दोनों श्रेणियों के संबंधित आवासों के लिए किराया 6 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह होगा। रिटेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले आवासों का मासिक किराया पहले 24 रुपए प्रति वर्गफीट निर्धारित था। अब इसे घटाकर 6 रुपए प्रति वर्गफीट किए जाने से आवासधारियों को सीधे 75 प्रतिशत की राहत मिलेगी।

खेत बचाओ अभियान-ग्राम मुरता में कृषक जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न

रायपुर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, रायपुर द्वारा संचालित खेत बचाओ अभियान-रबी 2026 के अंतर्गत सोमवार को जिला बेमेतरा के नवागढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत मुरता में कृषक जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुल 37 किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम में संस्थान वैज्ञानिक डॉ. विनोद कुमार वाशनिक एवं डॉ. आशीष मराठे ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, प्राकृतिक एवं जैविक खेती तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों के संबंध में विस्तृत



जानकारी दी। उन्होंने किसानों को रासायनिक उर्वरकों का संतुलित एवं आवश्यकता आधारित उपयोग करने, मृदा की उर्वरता बनाए रखने तथा फसल उत्पादन में प्राकृतिक एवं जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिकों एवं किसानों के बीच संवादात्मक परिचर्चा भी आयोजित की गई, जिसमें किसानों ने खेती से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं चुनौतियों पर चर्चा की। वैज्ञानिकों ने किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए स्थानीय कृषि परिस्थितियों के अनुरूप टिकाऊ एवं लाभकारी कृषि तकनीकों को अपनाने की सलाह दी।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.